▶▶ कृषि ▶▶ विश्लेषण ▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

अश्विन–कार्तिक 2080, नवंबर 2023

कहीं षडयंत्र तो नहीं, भुखमरी रिपोर्ट

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

दीपावली की

हार्दिक शुभकामनाएं

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और
पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

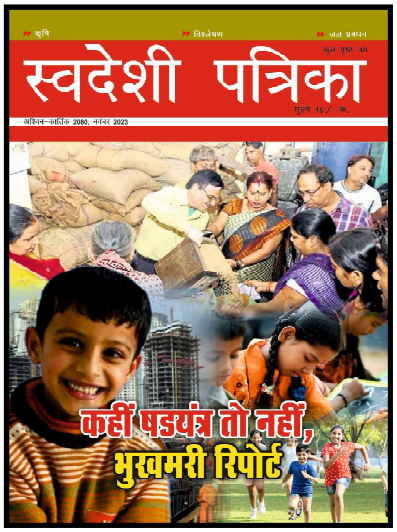

वर्ष–31, अंक–11
अश्विन–कार्तिक 2080 नवंबर 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 35-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–06
कहीं षडयंत्र तो नहीं, भुखमरी रिपोर्ट
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आर्थिकी
तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने की आशंका ..... अनिल तिवारी

10 विश्लेषण
भारतीय अर्थव्यवस्थाः सावधानी के साथ आशावाद ..... के.के श्रीवास्तव

12 रक्षा
उद्भव परियोजनाः प्राचीन ज्ञान और आधुनिक युद्ध ..... डॉ. जया कक्कड

14 मुद्दा
बंदूक संस्कृति छोड़ने को क्यों नहीं तैयार अमरीका? ..... विक्रम उपाध्याय

16 स्वदेशी
स्व–आधारित वैचारिक अधिष्ठान ..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

18 शिक्षा
घातक है विदेशों में पढ़ाई का क्रेज़ ..... स्वदेशी संवाद

20 स्वास्थ्य
भारत@2047: भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकी ..... डॉ. जया शर्मा

22 विमर्श
आतंक के रक्तबीज हमास के इज़राएल पर आक्रमण की पृष्ठभूमि ..... विनोद जौहरी

25 संस्कृति
वैश्विक स्तर पर नया आकार ले रहा है भारत का सांस्कृतिक वैभव ..... प्रहलाद सबनानी

27 खेती–बारी
किसान की जीवन निर्वाह आय यकीनी बनाएं ..... देविन्दर शर्मा

29 अर्थशास्त्र
सामाजिक एकता को गति देते भारतीय त्यौहार ..... डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह

31 पर्यावरण
पर्यावरण और जीवन ..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

33 आजकल
...फिर कांपी धरती तो उठे दहलाने वाले सवाल! ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

पाठकनामा

स्वदेशी – एक धर्म युद्ध

स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। धर्म से अभिप्राय है कि एक परम्परा को मानने वालों का समूह। समाज में व्यक्ति जीवन के प्रति जो धारणा बनाता है या धारण करता है, वही धर्म है। व्यापक अर्थ में धर्म का अर्थ हृदय की शुद्धी, साफ़ चरित्र, मन में आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करना है। धर्म अर्थात जो कोई वस्तु, मार्ग धारण करने योग्य हो, वही धर्म है। संसार में धारण करने के योग्य मात्र सत्य का मार्ग है, इसलिए सत्य ही धर्म है।

नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका यह सब पहले भारत का ही हिस्सा थे। समय के साथ स्वदेश घटता गया। नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध थे। माता सीता नेपाल नरेश राजा जनक की बेटी थी। धृत्तराष्ट्र की पत्नी गांधारी गंधार क्षेत्र की थी। भोजन में प्रयोग होने वाला सेंधा नमक सिंध में पाया जाता है जो उस कालखंड में भारत का हिस्सा था। महाभारत के अनुसार धार्मिक कृत्यों में स्वदेशी वस्तुओं का अति महत्व है। मृत्यु उपरान्त राजा पांडू की अस्थिओं को स्वदेश में निर्मित वस्त्र में लपेटकर रखने का वर्णन मिलता है।

आजकल त्यौहारों का महीना है। हर तरह के विदेशी माल से बाज़ार भरा पड़ा है। हम सभी को संकल्प लेना होगा कि कम से कम धार्मिक कृत्यों जैसे होली, दीपावली, गणेश उत्सव, दुर्गा अष्टमी में स्वदेश में बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। जब त्यौहार अपना है तो दिए, लाइट, पटाखें भी अपने होने चाहिये। बिना मज़बूत इछाशक्ति के यह धर्मयुद्ध लड़ना आसान नहीं है।

आर्थिक नीतियों के कारण हो सकता कि भारत सरकार की मजबूरियाँ हो किन्तु हम नागरिकों की कोई मजबूरी नहीं है। हमें अपने विवेक से काम लेना होगा और इस आर्थिक युद्ध में धर्म का साथ देना होगा। विदेशी ताकतें बाज़ार में नित नई चालें चल रही है। प्रधानमंत्री जी का नारा 'वोकल फॉर लोकल' तभी संभव है जब हम सभी का मानसिक परिवर्तन होगा। इस धर्मयुद्ध में बाबू गेनू की भांति कई शहीद भी होंगे लेकिन जब तक यह राष्ट्र रहेगा, स्वदेशी के लिए अपनी आहुति देने वालों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में सदैव लिखा जाता रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब 12 दिसंबर (बाबू गेनू शहीदी दिवस) की तिथि को पूरे देश में स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सुबोध कदशौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारत के प्रतिभाशाली और मेहनती युवा दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं और उन देशों में ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

द्रोपदी मुर्मू, महामहिम, भारत

हर बार की तरह इस बार भी त्योहारों में हमारी प्राथमिकता 'वोकल फॉर लोकल' होनी चाहिए।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

आज हमारा स्टैक, जो आधार, डिजिलॉकर, पेमेंट स्टैक है – इन तीनों को मिलाकर कोई भी समाधान तैयार किया जा सकता है। हमें ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के लिए बहुत अच्छा आकर्षण मिला है... हम इस क्षेत्र को एक के बाद एक क्षेत्र में दोहराने में सक्षम हैं और दुनिया इस पर ध्यान दे रही है।

अश्वनी वैष्णव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत

ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर एक और शरारती रिपोर्ट। एसजेएम इस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के खिलाफ अपनी गहरी पीड़ा दर्शाता है और भारत के देशभक्त लोगों से दुर्भावनापूर्ण इरादों वाली ऐसी रिपोर्टों (जारी) पर विश्वास न करने का आह्वान करता है।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

पश्चिमी दुनिया को अभी ऊंची ब्याज दरों के साथ जीना होगा

संयुक्त राज्य अमरीका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2023 में फेडरल फंड ब्याज दर को 5.25 से 5.50 की सीमा में रखा है। इससे पहले 11 बार से फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लगातार बढ़ाया था; और आज की ब्याज दर पिछले 22 वर्षों की अधिकतम दर पर है। हालांकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने भी अक्टूबर 2023 के लिए बीज ब्याज दर को पूर्ववत 4 प्रतिशत ही रखने का निर्णय किया है, लेकिन यह ब्याज दर पिछले 10 बार से लगातार बढ़ते हुए इस स्तर पर पहुंची थी। गौरतलब है कि अमरीका और यूरोप में इतनी ऊँची ब्याज दरें हाल ही के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। इन बढ़ती ब्याज दरों के कारण हर क्षेत्र में लोगों पर प्रभाव पड़ा है। अमरीका में गिरवी दर (मोर्टगेज रेट) 8 प्रतिशत पहुंच चुका है। क्रेडिट कार्ड पर औसत ब्याज दर 20 प्रतिशत, नई कार ऋण पर ब्याज दर औसतन 7.62 प्रतिशत और यहां तक कि विद्यार्थियों के लिए सरकारी ऋण की ब्याज दर 5.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। हालांकि अक्टूबर में अमरीकी और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर नहीं बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के लिए कुछ राहत का संकेत दिया है, लेकिन सरकारी हल्कों और विशेषज्ञों के बीच इस बात की सहमति दिखाई देती है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों के गिराये जाने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ऊर्जा और खाद्य महंगाई दर में कोई राहत दिखाई नहीं देती और युद्ध के रूकने के भी कोई आसार नहीं दिखते। यूं तो ऊपरी तौर पर नीतिगत ब्याज दर उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमरीका में फेडरल रिजर्व, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड आदि। लेकिन किसी भी देश में एक समय पर ब्याज दर का निर्धारण, उस समय की महंगाई की दर से प्रभावित होता है।

नीतिगत ब्याज दर को सामान्यतौर पर बैंक दर कहते हैं। इसके अलावा इसके कई अन्य संस्करण, जैसे रेपोरेट, रिवर्स रेपोरेट आदि भी उपयोग में आते हैं। मोटेतौर पर बैंक दर वो ब्याज दर होती है जिस पर उस देश के व्यवसायिक बैंक केन्द्रीय बैंक से ऋण ले सकते हैं। ये नीतिगत ब्याज दरें, देश में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें जैसे जमा पर ब्याज दर, उधार पर ब्याज दर आदि को प्रभावित करती हैं। यदि महंगाई दर ज्यादा हो और ब्याज दर कम हो, तो ऐसे में बचतों की राशि को जमा करने वाले लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जमा का वास्तविक मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार नीतिगत ब्याज दर, महंगाई की दर से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जमा करने वालों को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ लाभकारी ब्याज प्राप्त हो सके। एक उदाहरण के अनुसार यदि महंगाई दर 6 प्रतिशत है तो ऐसे में वास्तविक ब्याज दर 3 प्रतिशत रखने के लिए जमा पर ब्याज दर कम से कम 9 प्रतिशत होनी चाहिए। इसलिए महंगाई की स्थिति में नीतिगत ब्याज दरों का बढ़ाया जाना जरूरी हो जाता है।

एक तरफ जहां मंहगाई के घटने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, दुनिया भर के अमीर मुल्कों में मंदी की आशंकाएँ बढ़ती जा रही है। ब्याज दरों के बढ़ने के कारण घरों और कारों की ही नहीं बल्कि तमाम प्रकार की अन्य प्रकार की मांग भी प्रभावित हो सकती है। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर बढ़ने से घरेलू सामान की खरीद भी प्रभावित होने की आशंका है। जहां अमरीका में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश के प्रयास जोर पकड़ रहे थे, बढ़ती ब्याज दरें उस पर भी असर डाल सकती है। ऐसे में इन मुल्कों में मंदी की दस्तक महसूस की जा रही है। मंहगाई और ब्याज दरों में वृद्धि से विकासशील देश भी अछूते नहीं हैं। खाद्य मुद्रास्फीति और इंधन मुद्रास्फीति, दोनों ही विकासशील देशों को भी प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते मंहगाई की दर वहां भी ऊंची बनी हुई है। इसलिए विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी नीतिगत ब्याज दरों (ब्याज दर, रेपो रेट आदि) को लगातार बढ़ाया है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील में यह दर 12.75 प्रतिषत, साउथ अफ्रीका में 8.25 प्रतिषत, रूस में 15 प्रतिशत, चीन में 3.45 प्रतिशत और भारत में 6.5 प्रतिशत है। अन्य विकासशील देशों में से इंडोनेशिया में यह 6.0 प्रतिशत, मैक्सिको में 11.25 प्रतिशत है।

यह सही है कि भारत भी दुनिया की मंहगाई से अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी ईंधन मुद्रास्फीति और खाद्यस्फीति दोनों में भारत सबसे अधिक अछूता है। हालांकि अन्य देशों की भाँति आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भारत को भी बराबर प्रभावित कर रहे हैं। भारत अमरीका और यूरोपीय देशों के अवरोधों के बावजूद रूस से सस्ते पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में सफल रहा है। गौरतलब है कि पिछले समय में भारत रूस से पूर्व की तुलना में 50 गुणा से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। इस तेल की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में मात्र 60 प्रतिशत ही है और उसका भुगतान भी काफी हद तक डॉलरों में नहीं रूपये में किया जा रहा है। भारत में खाद्य पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, जिसका फायदा भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को हो रहा है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति दुनिया कई मुल्कों से काफी कम है। शायद यही कारण है कि दुनिया में जहां मंदी दस्तक दे रही है, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। भारत ने कृषि और सहायक गतिविधियों के अच्छे कार्य निष्पादन और स्वतंत्र विदेश नीति के चलते देश के आर्थिक हितों के संरक्षण के कारण भारत ने मुद्रास्फीति को काबू में रखा जा सका है। हमें समझना होगा कि अपने देश को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए, विदेशों पर निर्भरता को, खासतौर पर आपूर्ति श्रृंखला में, न्यूनतम करते हुए और दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ बराबरी के रिश्तों के साथ आगे बढ़ते हुए, हम, ब्याज दर को कम रखते हुए, दुनिया के समक्ष चुनौतियों से इतर अपनी अर्थव्यस्था को आगे बढ़ा सकते है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया को अभी कुछ समय तक ऊंची ब्याज दरों के साथ जीना सीखना होगा।

कहीं षडयंत्र तो नहीं, भुखमरी रिपोर्ट

पिछले सालों की तरह एक बार फिर जर्मनी की वेल्ट हंगरहिल्फे नाम की संस्था ने अपना 'हंगर इंडेक्स' और उस पर आधारित दुनिया के मुल्कों की भुखमरी रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में फिर से भारत को अत्यंत नीचे 111वें स्थान पर रखा गया है। गौरतलब है कि इस साल इस रैंकिंग में 125 देश शामिल किए गए हैं। पिछले साल 2022 में 121 मुल्कों की सूची में भारत को 107वें स्थान पर और उससे पिछले साल 2021 में 116 मुल्कों की रैंकिंग में भारत को 101वें स्थान पर रखा गया था।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस भुखमरी इंडेक्स से उनका अभिप्राय यह है कि भारत में भारी मात्रा में भुखमरी तो व्याप्त है ही, अन्य मुल्कों का प्रदर्शन भारत से कहीं बेहतर है। इस मामले में यदि रिपोर्ट को मानें तो पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशों का भी प्रदर्शन भारत से बेहतर है, जो भारत से खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट पर प्रश्न उठना स्वभाविक ही है। आईये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में भुखमरी और उसके सूचकांकों की वास्तविकता क्या हैं?

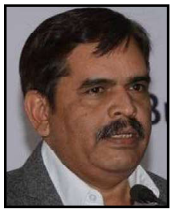

वेल्टहंगरहिल्फे की रिपोर्ट के बाद कई विरोधी राजनैतिक दलों ने भुखमरी को एक मुद्दा बनाया है। ऐसे में स्पष्ट है कि यह एजेंसी लगातार गलत आंकड़े और गलत मैथोडालॉजी का इस्तेमाल करते हुए, वास्तविकता से कहीं दूर भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की सभी एजेंसियों, जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है, के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
– डॉ. अश्वनी महाजन

क्या है वेल्ट हंगरहिल्फे का हंगर इंडेक्स

इस हंगर इंडेक्स को मापने के 4 पैमाने हैं – कुपोषण, बच्चों में ठिगनापन (स्टंटिंग), बच्चों का वजन (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) यानि वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर (5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर)। इन सभी पैमानों पर आधारित हंगर इंडेक्स को अनुमानित किया जाता है। वेल्ट हंगरहिल्फे का कहना है कि भारत में यह इंडेक्स 28.7 है, जो अत्यंत गंभीर है, जबकि पाकिस्तान में यह 26.6 है, जिसके कारण पाकिस्तान भी भारत से ऊपर 102वें पायदान पर है। इसी प्रकार बंग्लादेश 19.0 अंकों के साथ 81वें स्थान पर और श्रीलंका 13.3 अंकों के साथ 60वें स्थान पर बताया गया है।

हंगर इंडेक्स यानि भुखमरी सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त मापदंडों और पैमानों के बारे में बात करें तो एक तरफ आंकड़ों और दूसरी तरफ मैथोडोलोजी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। भारत सरकार ही नहीं कई विशेषज्ञ भी इस रिपोर्ट को सिरे से नकार रहे हैं।

बाल मृत्यु दर

इस सूचकांक का एक बड़ा हिस्सा बाल मृत्यु दर को लेकर है। वर्ष 2023 का भुखमरी सूचकांक बनाते हुए, 2020–21 की बाल मृत्यु दर का जो आंकड़ा लिया गया है। रिपोर्ट में भारत की बाल मृत्यु दर को 31 प्रति हजार बताया गया है।

भारत के नमूना रजिस्ट्रेशन प्रणाली द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2020 में बाल मृत्यु दर 35 प्रति हजार से घटकर 32 प्रति हजार पहुंच गई थी। यदि बाल मृत्यु दर की घटने की इसी दर को माना जाये तो वर्ष 2023 तक इसके 24.4 तक होने का अनुमान है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि भारत में बाल मृत्यु दर को 31 प्रति हजार माना जाये और देश को भुखमरी से पीड़ित बताने में पुराने आंकड़ों का उपयोग किया जाये।

ताजा आंकड़ों के अुनसार पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर 55.8 प्रति हजार है। बाल मृत्यु दर उससे भी कहीं अधिक है। इसके बावजूद भारत को भुखमरी के 111वें पायदान और पाकिस्तान को 102वें पायदान पर बताया जा रहा है। इसका कारण यह है कि भुखमरी सूचकांक के अन्य पैमानों में भी गलत आंकड़ों का उपयोग हुआ है।

कुछ खोट अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकडों में भी है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े जहां शिशु मृत्यु दर को 2020 में 28 प्रति हजार दिखा रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उन्हें अपने पुराने अनुमानों के आधार पर 29.848 बता रही हैं। गौरतलब है कि किसी भी विदेशी अथवा भारतीय एजेंसी को सरकार द्वारा प्रकाशित आंकडों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य आंकड़ों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन हंगर इंडेक्स की यह रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है कि जरूरी नहीं कि इस रिपोर्ट में सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़े ही प्रयुक्त किए गए हैं। भारत में तेजी से सुधरती स्थितियां शायद कुल्सित ऐजेंडा के साथ काम करने वाली संस्थाओं को रास नहीं आ रही।

कुपोषण

जहां तक कुपोषण पर आंकड़ों का प्रश्न है, वेल्ट हंगरहिल्फे के पास कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि संबंधित एजेंसी द्वारा गृहस्थ उपभोग सर्वेक्षण 2011 के बाद हुआ ही नहीं। इसलिए 3000 लोगों के नमूने पर एक 'गैलप सर्वेक्षण', जिसकी कार्यप्रणाली भी संदिग्ध है, उसके आधार पर कुपोषण के आंकड़े तैयार किए गए हैं। अगर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपलब्धता की बात करें तो आज 188 देशों की उपलब्ध नवीनतम वैश्विक रैंकिंग (2020) में भारत का स्थान दुनिया में 35वां है। लगातार बढ़ता प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, दूध, अंडे, फल–सब्जी, मछली आदि सभी पदार्थों का उत्पादन इस बात की पुष्टि करता है कि भारत आज मांग की तुलना में अधिशेष का उत्पादन कर रहा है।

ठिगनापन और पतलापन (स्टंटिंग और वेस्टिंग)

देश में कुछ समय पूर्व तक एकमात्र नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वेक्षण द्वारा आकलित स्टंटिंग और वेस्टिंग के आंकड़े ही उपलब्ध थे। लेकिन छोटे सैंपल आकार के चलते, उन पर कई बार प्रश्नचिन्ह लगते थे। भारत सरकार के महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा देश के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक पोषण अभियान की शुरूआत की गई है। एनएफएचएस में अपेक्षाकृत छोटे सैंपल के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते थे, पोषण ट्रैकर में 7 करोड़ से अधिक बच्चों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आंकड़े प्रकाशित किए जा रहे हैं, जहां वेस्टिंग के आंकड़े लगातार बता रहे हैं कि भारत के बच्चों में मात्र 7.2 प्रतिशत वेस्टिंग ही है, जबकि वेल्ट हंगरहिल्फे की भुखमरी रिपोर्ट (2023) में एनएफएचएस 2019–21 का 18.7 प्रतिशत वेस्टिंग का आंकड़ा प्रयुक्त हुआ है।

जहां तक ठिगनेपन यानि स्टंटिंग का सवाल है, विशेषज्ञों को मानना है कि पूरे देश के लिए कद का एक मानक नहीं हो सकता। ठिगनापन ही नहीं पतलापन भी भौगोलिक क्षेत्र, पर्यावरण, आनुवंशिक और पोषण जैसे कई तत्वों पर निर्भर करता है। यदि कद की बात की जाए तो पंजाबी बच्चों का कद पूर्वोत्तर के बच्चों से कई इंच ज्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इसलिए वेल्ट हंगरहिल्फे द्वारा प्रकाशित भुखमरी सूचकांक भारत की गलत तस्वीर पेश कर रहा है।

गौरतलब है कि वास्तविक तौर पर 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य आंकड़ों के आधार पर बने पोषण ट्रैकर के आधार पर देखा जाए तो देश में फरवरी 2023 में मात्र 7.7 प्रतिशत बच्चे ही कुपोषित थे। जबकि गैलप सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कुपोषण का प्रमाण 16.6 प्रतिशत बताया जा रहा है।

यही नहीं कि भारत सरकार का पोषण अभियान देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए कार्यरत है, और इसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी करने लगा है। हालांकि वेल्ट हंगरहिल्फे की रिपोर्ट की मैथोडोलॉजी पर भी कई सवाल हैं, लेकिन फिर भी यदि भुखमरी सूचकांक निकालने के लिए जो फार्मूला एजेंसी द्वारा उपयोग किया गया है, उसी को मानते हुए यदि सही आंकड़ों यानि बाल मृत्यु दर 24.4 प्रति हजार, 5 साल के बच्चों का पतलापन यानि वेस्टिंग को पोषण ट्रैकर द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार 7.2 प्रतिशत माना जाए और कुपोषण को पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार 7.7 माना जाए, और चूंकि स्टंटिंग के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, तो इस लेख के लेखक द्वारा भुखमरी सूचकांक का जो आंकड़ा प्राप्त होता है वह 9. 528 निकलता है। इस हिसाब से, वेल्ट हंगरहिल्फे के फार्मूले के अनुसार भी भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 111वीं नहीं बल्कि 48वीं प्राप्त होती है।

स्वाभाविक ही है कि वेल्ट हंगरहिल्फे की रिपोर्ट के बाद कई विरोधी राजनैतिक दलों ने भुखमरी को एक मुद्दा बनाया है। ऐसे में स्पष्ट है कि यह एजेंसी लगातार गलत आंकड़े और गलत मैथोडालॉजी का इस्तेमाल करते हुए, वास्तविकता से कहीं दूर भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की सभी एजेंसियों, जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है, के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ❑❑

तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने की आशंका

इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का असर अब दुनिया भर में दिखने लगा है। इस जंग से भारत की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इसराइल–हमास युद्ध के कारण कच्चे तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के चलते तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर की ओर जा रही है वहीं वैश्विक खाद्यान्न संकट के मद्देनजर खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका भी गहरा रही है। हालांकि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में थोक एवं खुदरा महंगाई के सूचकांक, महंगाई में कमी का संकेत दे रहे हैं लेकिन चुनौती पूर्ण वैश्विक भू–राजनीतिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के दौर में महंगाई के बढ़ने की आशंका अधिक है।

मालूम हो कि युद्ध के चलते तेल उत्पादक देशों द्वारा की जा रही कटौती के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति घटने और उसकी कीमतों के ऊपर जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें इस साल लगभग 28 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड वायदा 94 डालर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिसके युद्ध न रुकने की स्थिति में जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल होने की बात कहीं जा रही है। तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं।

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022–23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 10.02 प्रतिशत बढ़ी जिसके कारण पेट्रोल में 13.4 प्रतिशत, डीजल में 12 प्रतिशत और एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 में घरेलू उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आने से आयातित कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता बढ़कर 87.8 प्रतिशत हो गई है। रियायती रूसी आपूर्ति के बावजूद हमारा वार्षिक कच्चे तेल का आयात 158 बिलियन डॉलर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत ज्यादा है। मात्रा के लिहाज से कच्चे तेल का आयात 9.4 प्रतिशत बढ़कर 232.4 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई,और उनके आयात में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन निर्यात में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

रूस–यूक्रेन के बीच पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के दौरान ही इसराइल–हमास के बीच युद्ध के गहराने की आशंका के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए कारगर रणनीतिक प्रयास बहुत जरूरी है।

–अनिल तिवारी

इसराइल हमास के बीच जारी जंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है क्योंकि युद्ध के चलते महंगाई बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया तो कच्चे तेल की आपूर्ति अवश्य बाधित होगी जिसके कारण तेल की कीमतों में और अधिक तेजी आएगी। भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है रोजमर्रा की चीजों में महंगाई का बढ़ना। चूंकि महंगाई मध्यम वर्ग को अधिक प्रभावित करती है। इसलिए अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई को बांधे रखना सरकार के लिए एक कठिन चुनौती की तरह है। पिछले दिनों विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी दुनिया के साथ–साथ भारत में भी महंगाई के बढ़ाने की चुनौती प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2023–24 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है। पूर्व में प्रस्तुत महंगाई के अनुमान से नया अनुमान अधिक बताया गया है। सितंबर महीने में रासायनिक उत्पादों, खनिज, तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जुलाई 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, वह अगस्त 2023 में घटकर 6.8 प्रतिशत और सितंबर में 5. 02 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह कमी अनाज, सब्जी, परिधान, फुटवियर, आवास एवं सेवाओं की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हुई है। बीते 6 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को 6. 5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सार्थक प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। खास तौर से गेहूं के दाम नियंत्रण के लिए खुले बाजार में मांग की पूर्ति के अनुरूप इसकी अधिक बिक्री जरूरी है।

महंगाई को लेकर चुनौतियां लगातार बड़ी हो रही हैं। पिछले माह ज्यादातर समय कच्चे तेल का दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर रहा, अब यह और बढ़कर 94 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया भर के बाजारों में गेहूं, दाल और चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। चीनी की कीमतें 12 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अक्टूबर महीने में त्यौहारी मांग बढ़ने से दालों के दाम भी ऊंचे हुए हैं। 18 अक्टूबर 2023 को सरकार के द्वारा प्रकाशित खाद्यान्न उत्पादन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022–23 में गेहूं का उत्पादन अनुमानित लक्ष्य से 20 लाख टन घटकर 11.5 करोड़ टन, दालों का उत्पादन 2.7 करोड़ टन घटकर 2.6 करोड़ टन और चावल का उत्पादन पिछले वर्ष के 13.94 करोड़ टन से घटकर 12.98 करोड़ टन होने का अनुमान है। हालांकि केंद्र की सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सार्थक प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। खास तौर से गेहूं के दाम नियंत्रण के लिए खुले बाजार में मांग की पूर्ति के अनुरूप इसकी अधिक बिक्री जरूरी है। आटा मिलों को अधिक मात्रा में गेहूं दिया जाना चाहिए। साथ ही गेहूं के शुल्क मुक्त आयत की अनुमति दिए जाने की भी जरूरत है। देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार को और तेजी लानी होगी। अतिरिक्त नगदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को खासा ध्यान देना होगा।सरकार द्वारा खुदरा महंगाई के नियंत्रण के लिए रणनीतिक रूप से एक ऐसी मूल्य नियंत्रण समिति का गठन करने पर विचार करना होगा जो बाजार में आने वाले उतार–चढ़ाव को देखते हुए कीमतों के अनियंत्रित होने से पहले ही मूल्य नियंत्रण के कारगर कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर दिखे। रूस–यूक्रेन के बीच पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के दौरान ही इसराइल–हमास के बीच युद्ध के गहराने की आशंका के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए कारगर रणनीतिक प्रयास बहुत जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार देश के मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को महंगाई की मार से बचाने के लिए ठोस कार्य नीति के साथ आगे आएगी। ❑❑

भारतीय अर्थव्यवस्थाः सावधानी के साथ आशावाद

नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2047 तक यानी कि भारत की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे, भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में यह 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2030 तक भारत, जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। एस. एंड पी. का अनुमान है कि भारत की नाम मात्र की जीडीपी जो 2022 में 3.4 ट्रिलियन डॉलर थी, बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की होने जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 से 2030 तक 9 प्रतिशत, वर्ष 2030 से 2040 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 9.5 प्रतिशत तथा 2040 से 2047 के बीच 8.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ती रहे। लेकिन इसके लिए हमें व्यापक सुधार करने होंगे। अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रासंगिक कार्य क्षेत्र और रणनीति की भी पहचान करनी होगी जिसमें मानव पूंजी का निर्माण, पोषण और भारत की विशाल बाजार क्षमता का लाभ उठाना तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार शामिल करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि भारत अपनी आजादी के 100 वर्षों के भीतर यह सब कर लेता है तो भारत को विकसित राष्ट्र का तमगा मिल जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का योगदान बढ़कर 18 प्रतिशत होगा। उम्मीद है कि वर्ष 2023 और 2024 में भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया की आधी वृद्धि में योगदान देंगे, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत से अधिक की होगी।

वर्तमान में लचीली घरेलू मांग और बड़े सार्वजनिक पूंजी व्यय दोनों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। जनसंख्या लाभांश, डिजिटलीकरण आदि के कारण भारत स्थिर गति से बढ़ रहा है। हालांकि अधिक संरचनात्मक सुधार किए जाते, एफडी मानदंडों को आसान बनाया जाता, श्रम बल को कुशल तकनीक से लैस किया

आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में नकारात्मकता के कुहासे के बीच भारत की स्थिति एक चमकते सितारे की है। लेकिन आने वाले दिनों में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अभी और प्रयास करने की जरूरत है।

– के.के. श्रीवास्तव

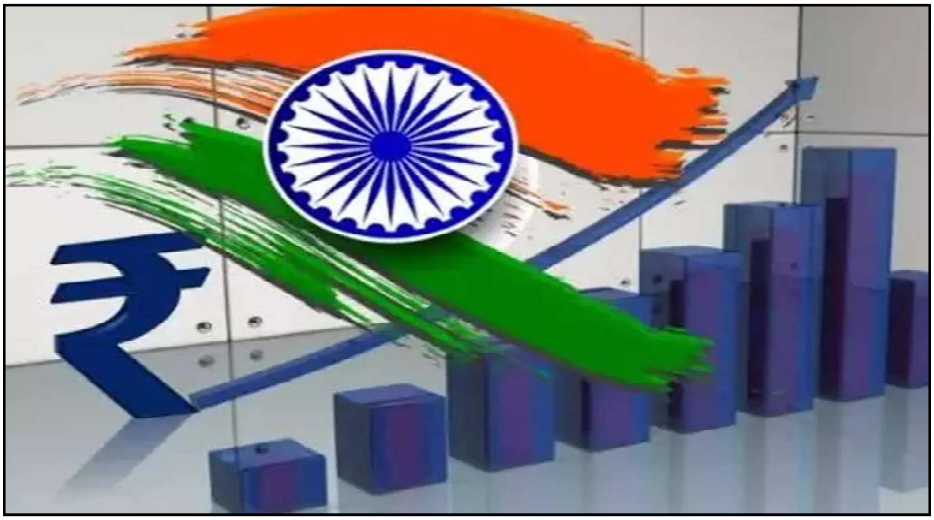

जाता और वित्तीय प्रणाली को और मजबूत किया जाता तो विकास की गति और अधिक बढ़ सकती है।

हालांकि वित्तमंत्री ने घरेलू मैक्रो–फंडामेंटल के मजबूत होने तथा उनमें लगातार सुधार का दावा करते हुए आशावाद की एक गुलाबी तस्वीर पेश की है लेकिन हम वैश्विक अनिश्चितताओं और मौसम संबंधी मुद्दों से होने वाली गिरावट के जोखिम को कम नहीं आंक सकते। एस. एंड पी. ने भी तेज डिजिटल परिवर्तन और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग से भारत को आगे ले जाने की उम्मीद जताई है। उसका मानना है कि वर्ष 2030 तक केवल अमेरिका और चीन के बाद जर्मनी और जापान को पछाड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन निकट भविष्य के परिदृश्य के बारे में भी हमें चौकस रहना होगा।

यह सच है कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, आवासीय संपत्तियों की मांग, निवेश की बढ़ती मांग जैसे संकेतक समान स्तर पर हैं लेकिन एक सच यह भी है की आय वृद्धि लगातार धीमी रही है, इससे निजी उपभोग और निवेश की वृद्धि भी निचले स्तर पर आई है। महंगाई पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री कीन्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मित्तव्ययिता के विरोधाभास से पीड़ित है? क्योंकि कम विकास वाली अर्थव्यवस्था में लोग डर के मारे कम खर्च करते हैं इससे आय कम होती है और खर्च भी कम होता है लेकिन इससे एक प्रकार का ऐसा दुष्चक्र उभरता है जिससे पार पाना काफी कठिन होता है।

वर्तमान में भारत में न केवल खपत कम है बल्कि बचत भी कम है। उच्च मुद्रास्फीति की उपस्थिति में वास्तविक आय लगातार गिर रही है। तीन बेडरूम वाले घर, एसयूबी गाड़ियों की मांग बढ़ी है लेकिन मोटरसाइकिल और अन्य दो पहिया वाहनों की मांग उतनी मजबूत नहीं है। वास्तविक आय के अभाव में लोग जो भी खर्च कर रहे हैं वह शायद ऋण के कारण कर रहे हैं। यह अच्छा संकेतक नहीं है। यदि हम अपने अल्पावधि का ध्यान नहीं रखते हैं तो जैसा कि कींस ने कहा था दीर्घावधि में हम सभी मृत हैं। इसलिए अनुमानित 6 प्रतिशत से अधिक की विकास दर पर इतराने वाली बात को गंभीरता से लेना होगा। अनुमानित विजन दस्तावेज को परखने की जरूरत है। हमें इसके लिए हर साल समीक्षा करनी होगी, तभी हम 47 तक लक्ष्य पर पहुंचेंगे और विकसित राष्ट्र कहलाएंगे।

पिछले कुछ समय से वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है। 2021 की महामारी ने सबको हिला कर रख दिया। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण के कारणआपूर्ति श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गई और आर्थिक नेटवर्क एक तरह से बाधित हो गया। इसके चलते आवश्यक उपभोक्ता सामान के दाम में भारी उछाल आ गया। अधिकांश केंद्रीय बैंकों को बेंचमार्क ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी इससे आर्थिक गतिविधियां तो धीमी हुई ही बाजारों में भी अस्थिरता आ गई। अब इसराइल और हमास का संघर्ष सबको सकते में डाल रखा है। इसके कुछ कारक निश्चित रूप से भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे विश्व बैंक ने पहले ही इसकी आशंका जाता दी है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक अमेरिकी बांड बढ़ा रहा है इसका मतलब है कि एफपीआई फंड भारत से बाहर जा सकता है। इससे रुपए की सराहना बढ़ेगी इसके परिणाम स्वरुप आयत की उच्च लागत, प्रतिकूल भुगतान संतुलन और घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। इसी तरह इजराइल हमास युद्ध अन्य मध्य पूर्वी देशों को अपनी चपेट में ले लेता है तो तेल की कीमतों पर अनिश्चितता होगी।

भारत के लिए अनुमानित 6 प्रतिशत से अधिक की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है। हमें याद रखना होगा और विजन दस्तावेज भी कहता है कि हमें अब और 2047 के बीच औसतन 8 प्रतिशत के दर से बढ़ने की जरूरत है ताकि भारतीयों के व्यापक समूह के लिए समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

निश्चित रूप से अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में हमें कई बाधाओ से पार पाना है, जिनमें से कई निश्चित रूप से आयातित है। सुस्त वैश्विक मांग के कारण हमारा निर्यात लड़खड़ा रहा है। एक संकेतक यह है कि जहां श्रम बल भागीदारी दर ऊपर की ओर बढ़ी है वही एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वरोजगार के रूप में उभरा है। इसका एक मतलब यह भी है कि अर्थव्यवस्था श्रम बल में प्रवेश करने वाले नए लोगों के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि मनरेगा के तहत काम की मांग महामारी से पहले के स्तर से अब भी अधिक बनी हुई है। ग्रामीण मांग दबाव में है। यह महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित होने के बाद अब तक ठीक से उबार नहीं पायी है। वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही में बे–मौसम बारिश के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ उत्पादन कम हुआ और उनकी आय में भी कमी आई है।

ऐसे में हमें सावधानी और आशावाद के साथ दिवाली मनाने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपने प्रतिद्वंद्वी चीन सहित कई अन्य देश से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। खासकर तब जब हमारा 2047 तक विकसित देशों की कतार में शामिल होने का बड़ा लक्ष्य तय है। ❑❑

उद्भव परियोजना

प्राचीन ज्ञान और आधुनिक युद्ध

भारत में सबसे पहला युद्ध संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान लड़ा गया था। इस परिकल्पना की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। इसके बाद आर्यों ने मूल निवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में प्राचीन काल के दौरान रामायण और महाभारत के महाकाव्य में उस समय के युद्ध व्यापार का विवरण मिलता है। सभी कालों में विभिन्न संप्रदायों के युद्ध लड़े गए और इन युद्धों के तत्कालीन वृतांत उस समय के दौरान प्रचलित युद्ध की कला की जानकारी प्रदान करते हैं। उन सभी युद्धों में एक तरफ सैनिकों और जानवरों को प्रशिक्षित किया गया तो लगे हाथों विरोधी अर्थव्यवस्था को हराने के लिए रणनीतियां और युक्तियां भी तैयार की गई।

प्राचीन काल में शारीरिक फिटनेस पर बहुत जोर दिया जाता था। मानसिक और शारीरिक चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए खेलों की एक समृद्ध परंपरा थी। सैन्य रणनीति एवं रणनीति के आसपास विशिष्ट खेल बनाए गए थे जैसे चतुरंग, अष्ट पद, तीरंदाजी आदि। इसके अलावा अधिकारियों, पुरुषों और संचालकों को उनके काम के लिए विशिष्ट विषय सिखाए जाते थे, उदाहरण के लिए एक घोड़ा संचालक जानवरों के व्यवहार उसके नियंत्रण आदि के बारे में सीखना था। अधिकारियों को युद्ध कानून और न्याय के बारे में ज्ञान होना आवश्यक था। सैनिकों को सिखाया जाता था कि व्यक्तिगत रूप से और लड़ाकू इकाइयों के रूप में युद्ध कैसे लड़ना है। गुरुकुलों में धनुर्वेद या हथियारों से लड़ने की कला कुछ चुनिंदा लोगों को सिखाई जाती थी।

सैनिक रणनीति का विकास सैन्य विज्ञान के रूप में किया गया जिसका वर्णन अग्नि पुराण, अर्थशास्त्र तथा अन्य ग्रंथों में मिलता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ''उद्भव परियोजना'' शुरू की, जो कूटनीति, शासन काल, रणनीति और युद्ध के क्षेत्र में प्रासंगिक सबक लेने के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित है। इस योजना के जरिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखने के लिए अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, थिरुकुरल और अन्य का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया जाएगा। यह वर्तमान शासन की सोच के अनुरूप

प्राचीन ज्ञान कहीं से भी उपहास करने योग्य नहीं है इसे लाभप्रद रूप से आत्मसात किया ही जाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा की विश्व अब एक अलग तरह का युद्ध क्षेत्र बन चुका है, इसलिए हमें देश काल परिस्थिति के मुताबिक खुद को अद्यतन करने की भी आवश्यकता है।

– डॉ. जया कक्कड़

है कि हमारा प्राचीन अतीत ज्ञान और बुद्धिमत्ता का बहुत समृद्ध भंडार था, जिसे फिर से तलाशने, दोबारा देखने और पुनर्वास करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या यह प्राचीन विचारक जैसे कि चाणक्य और कामन्दक आधुनिक जनरलों की सहायता के लिए आगे आ सकते हैं? या क्या यह पाठ आधुनिक युद्ध के प्रबंधन में आत्म बधाई संदेश को छोड़कर बहुत कम मदद करेंगे? भारतीय सेवा ने पूरे अहंकार के साथ स्वदेशी सैन्य प्रणालियों उनके मूल्यांकन रणनीतियों और सहस्त्राब्दियों से भूमि पर शासन करने वाली रणनीतिक विचार प्रक्रियाओं की गहराई में जाने का फैसला किया है। इसके अलावा इसका इरादा शास्त्रीय शिक्षण को फिर से शुरू करना और प्राचीन ज्ञान सृजन को पुनर्जीवित करना भी है।

निश्चित रूप से अर्थशास्त्र में राज्य निर्माण, भू–रणनीति और सैन्य युद्ध में मूल्यवान अंतर दृष्टि शामिल है। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ दक्षिण में भी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सेना का कहना है कि इसके लिए आठवीं सदी से पहले लिखे गए शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा। इस अवधि के बाद के ग्रंथ क्यों नहीं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की बाद की अवधि जैसे 11वीं और 15वीं शताब्दी महान सैन्य परिवर्तनों की गवाह रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्थशास्त्र राज्य निर्माण के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है लेकिन वर्तमान संदर्भ में नहीं। अर्थशास्त्र जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कीमत, यहां तक कि अत्यधिक हिंसा को भी काफी बड़ा नहीं मानता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आधुनिक लोकतंत्र में अर्थशास्त्र को किस हद तक प्रसांगिक बनाया जा सकता है? और क्या आठवीं शताब्दी के शास्त्रीय काल के बाद शासन करने वाली राजनीति और ग्रंथ जैसा कि भारतीय सेना द्वारा परिभाषित किया गया है। आधुनिक शासन काल के लिए महत्वपूर्ण सबक लेने के लिए अप्रासंगिक है? निश्चित रूप से यह मध्य युगीन साम्राज्य ही थे जिन्होंने उन्नत घुड़सवार, सेना बंदूक शक्ति, रणनीति आदि का विकास देखा इनमें से कई को भारतीय सेना द्वारा अनुकूलित किया गया है इसलिए प्राचीन काल पर ध्यान केंद्रित करना कुछ हद तक अदूरदर्शिता पूर्ण लगता है। लेकिन सबसे बड़ी आपत्तियां इस तथ्य के रूप में सामने आती हैं कि प्राचीन ग्रंथो में राज्य के बारे में वैसा लिखा गया जैसा उसे होना चाहिए ना कि राज्य के बारे में जैसा वह था। उन सभी ने एक अधिनायक वादी राज्य को ध्यान में रखा जिसका उद्देश्य एक ही था हर कीमत पर अपनी सीमाओं को जारी रखना और उसका विस्तार करना। फिर भी सब अप्रासंगिक नहीं, इनमें से कुछ अध्ययन काम आएंगे।

आयोजित युद्ध की उत्पत्ति मोटे तौर पर नेपोलियन युग में हुई थी जिसमें मोबाइल तोपखाने, पैदल सेना, घुड़सवार सेना को रसद सामग्री और इंजीनियरों के ढांचे से समर्थित किया गया था। बाद के दिनों में टेलीग्राफ और परिवहन के बेहतर साधनों के साथ राइफल, मशीन गन जैसे कई परिष्कृत हथियार सामने आए। इससे युद्ध क्षेत्र और सैन्य रणनीति दोनों बदल गई। आज के युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन चलाने वाले जनरल और एडमिरल सैन्य विचारों द्वारा तैयार की गई रणनीतियों द्वारा निर्देशित होते रहते हैं जिन्होंने युद्ध के इस नए रूप का अध्ययन किया है।

बाद में दुनिया ने दो बड़े विश्व युद्ध देखें जिसने कई देशों को तबाह कर दिया और उनकी सेना और संबंधित रणनीतियों को नया रूप दिया। परमाणु हथियारों की खोज को जोड़ा गया जिससे एक दूसरे के खिलाफ सक्रिय शारीरिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध शीत युद्ध के युग की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि परमाणु की खोज के बाद सक्रिय शारीरिक झड़पें, लड़ाइयां, युद्ध एक साथ गायब हो गए। रूस यूक्रेन और इसराइल हमास का संघर्ष इस बात के गवाह है।

मुख्य बात यह है कि अब युद्ध कई मोर्चे पर लड़ा जा रहा है जिनमें कई बार अपने मोर्चों पर भी युद्ध लड़ना पड़ता है। आज ऐसा कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे युद्ध क्षेत्र के रूप में सीमा अंकित किया जा सके, ऐसी स्थिति में मानव मस्तिष्क या प्रौद्योगिकी समर्थन की कोई भी मात्रा राष्ट्र के दुश्मन का मुकाबला करने में सत्तारूढ़ स्वभाव की सहायता के लिए आगे नहीं आ सकती है। आज कोई भी रणनीति पर्याप्त नहीं है तो प्राचीन ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। प्राचीन ज्ञान हमारे सेना अध्यक्षों को आज के संदर्भ में सामरिक सहायता प्रदान करने में कई बार सफल हो सकता है क्योंकि अब सुरक्षा के भी ढेर सारे मोर्चे हैं। प्राचीन ज्ञान अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन रोज–रोज जटिल हो रही दुनिया अद्यतन ज्ञान के भरोसे ही आगे बढ़ सकती है। प्राचीन ज्ञान में कुछ सीखने लायक हो तो अवश्य सीखा जाना चाहिए लेकिन प्राचीन के भरोसे बैठकर आज की दुनिया से लड़ना असंभव जैसा है। इसलिए सीखने का शुद्ध सबक यह है कि प्राचीन ज्ञान यदि कुछ काम का है तो उसे हमें जानना चाहिए तथा आधुनिक सैन्यकला में पारंगत सेनानायकों को लाभप्रद चीजेंबतानी चाहिए लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे नायकों को आज की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और विचारों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आधुनिक युद्ध के बारे में प्राचीन और मध्ययुगीन सभी कालों के ज्ञान को अतीत के ज्ञान के साथ पूरा करने की आवश्यकता है।❑❑

बंदूक संस्कृति छोड़ने को क्यों नहीं तैयार अमरीका?

अमेरिका के लेविस्टन में हुई गोलीबारी के आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस सिरफिरे ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 लोगों को मार दिया। अब वहां फिर से इस बात पर बहस हो रही है कि क्या गन कल्चर को ख़त्म करने के लिए तत्काल कड़ा कानून लाया जाए। क्योंकि कुछ महीने पहले ही अमरीका के मेने राज्य के विधानमंडल में बंदूक खरीदने या रखने पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से तीन प्रमुख विधेयकों को ख़ारिज कर दिया गया था।

ये विधेयक आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के लिए बंदूक खरीद से पहले गहन जांच की आवश्यकता, बंदूक खरीदने के बाद भी उसकी सुपुर्दगी से पहले 72 घंटे की प्रतीक्षा और अर्धस्वचालित हथियारों को रखना गैरकानूनी घोषित करने से संबंधित थे। ये तीनों बिल मेन सीनेट में बड़े अंतर से गिर गए। पता है क्यों? क्योंकि अधिकतर सीनेट सदस्य का मानना है कि उनके क्षेत्र में शिकार की संस्कृति है और बंदूक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का मतलब उनके लिए बुरे दिन जैसा है।

लगातार शूट आउट की घटना

अमेरिका में बिना कारण शूट आउट की यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही मेन में जेल से रिहा हुए एक व्यक्ति ने अपने माता–पिता और दो दोस्तों की हत्या कर दी। इसी अप्रैल में कंबरलैंड और सगादाहोक काउंटियों में एक राजमार्ग पर मोटर चालकों पर गोली चलाने की घटना हुई। जाहिर है अभी जो कानून हैं वह किसी बंदूकधारी को हिंसा से रोकने में कारगर नहीं हैं। मेने के ग्रामीण क्षेत्रों में बंदूक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रैंड कॉर्पोरेशन के 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, 2006 और 2017 के बीच मेन के 45 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक बंदूक थी, जबकि पूरे अमेरिका में लगभग 32 प्रतिशत परिवारों के पास कोई न कोई आग्नेयशस्त्र जरूर है। यहां गन कल्चर इतना हावी है कि हथियारों की बिक्री आम दुकानों पर बिना रोक टोक के होती है। फ्लोरिडा में

बंदूक कल्चर को नियंत्रित करना दुनिया भर में एक मुद्दा है। अधिकतर औद्योगिक देशों में बंदूक–नियंत्रण के सख्त नियम हैं। जापान में सीमित मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों को प्राप्त करने और उसके उपयोग पर प्रतिबंध है।

– विक्रम उपाध्याय

पिछले दिनों एक व्यक्ति की फोटो दुकान से हैंडगन की खरीदारी करते हुए प्रकाशित हुई थी।

अमेरिकी समाज और बंदूक का अधिकार

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हथियार रखने के अधिकार की गारंटी देता है। 15 दिसंबर 1791 को संविधान के दूसरे संशोधन के जरिए यह अधिकार अमेरिकी नागरिकों को दे दिया गया था। आज लगभग एक तिहाई अमेरिकी वयस्कों के पास उनका व्यक्तिगत हथियार है। अब बंदूक से बढ़ती मृत्यु दर और बड़े पैमाने पर गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन भी एक बंदूक नीति के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं।

पिछले साल जून में अमेरिकी कांग्रेस में बंदूक सुरक्षा बिल पारित कराया गया था। दशकों में पारित यह विधेयक भी हथियार पर प्रतिबंध लगाने में विफल रहा, लेकिन इसमें स्कूल सुरक्षा को लेकर कुछ वित्त पोषण के प्रावधान शामिल किए गए। कैलिफ़ोर्निया, डेलावेयर और न्यूयॉर्क सहित कुछ अन्य राज्यों ने बंदूक हिंसा को रोकने में मदद करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं।

चौंकाने वाले आंकड़े

जून 2023 में प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिका में बंदूक संस्कृति पर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें चौकाने वाले तथ्य सामने आए। दस में से चार अमेरिकी वयस्कों का कहना है कि वे अपने घर में बंदूक अवश्य रखते हैं। 32 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उनके पास व्यक्तिगत रूप से एक बंदूक है। आम नागरिक ही नहीं अमेरिकी राजनीतिज्ञ भी बंदूक रखने में पीछे नहीं हैं। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े 45 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उनके पास हथियार है, 20 प्रतिशत डेमोक्रैट भी मानते हैं कि उन्होंने भी हथियार रखा हुआ है। बंदूक रखने वालों में 40 प्रतिशत पुरुष हैं जबकि महिलाओं का प्रतिशत 25 है।

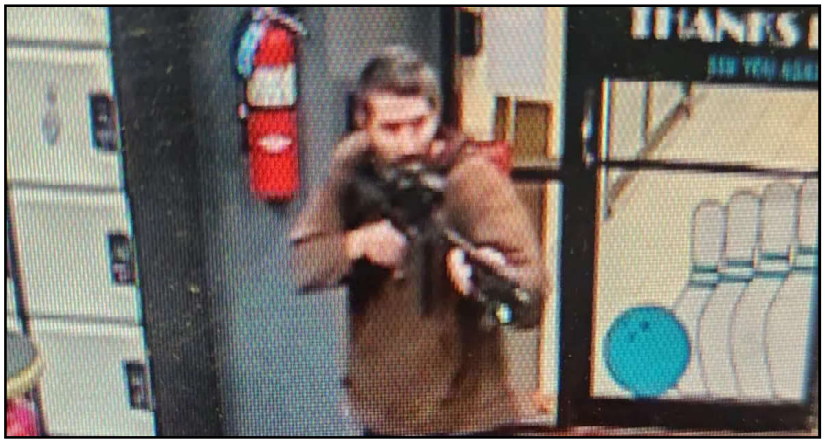

अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 47 प्रतिशत वयस्कों के पास व्यक्तिगत हथियार हैं, तो उपनगरों में रहने वाले 30 प्रतिशत लोगों के पास।

इसी तरह अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 47 प्रतिशत वयस्कों के पास व्यक्तिगत हथियार हैं तो उपनगरों में रहने वाले 30 प्रतिशत लोगों के पास। हां शहरी क्षेत्रों में केवल 20 प्रतिशत लोग ही हथियार रखते हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार 32 प्रतिशत अमेरिकी शिकार करने के लिए बंदूक रखते हैं। बंदूक के प्रति प्रेम कितना अधिक है यह इस बात से पता चलता है कि जिन रिपब्लिकन के पास कोई हथियार नहीं है उनमें से 61 प्रतिशत और डेमोक्रेट के 40 प्रतिशत यह कहते हैं कि वे भविष्य में बंदूक रखने पर विचार करेंगे।

दुनिया भर में चिंता

यह जानते हुए भी कि बंदूक के प्रति क़ानूनी ढ़ील के कारण लोंगों की जिंदगी अकारण जा रही है, अमेरिकी इस पर प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऑस्ट्रेलिया में बदूक प्रतिबंध पर खुशी जताते हुए 26 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में कहा भी – "आज हमारे देश में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण बंदूक हिंसा है। बंदूक हिंसा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे कई समुदायों को आतंकित किया है और आघात पहुँचाया है।" उल्लेखनीय है कि अब ऑस्ट्रेलियाई कानून में नागरिकों को यह साबित करना आवश्यक है कि उनके पास बंदूक रखने का वास्तविक कारण है। अब वहां आत्म–सुरक्षा को वास्तविक कारण नहीं माना जाता है।

बंदूक कल्चर को नियंत्रित करना दुनिया भर में एक मुद्दा है। अधिकतर औद्योगिक देशों में बंदूक–नियंत्रण के सख्त नियम हैं। जापान में सीमित मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों को प्राप्त करने और उसके उपयोग पर प्रतिबंध है। कनाडा में प्रतियोगिताओं और अभ्यास के लिए आग्नेयास्त्रों को रखने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन हैंडगन के सख्त नियम हैं। जब तक कि व्यक्ति यह विश्वास न दिला दे कि आत्मरक्षा के लिए हैंडगन की उसे वाकई आवश्यकता है, तब तक उसे हथियार नहीं दिया जाता। यूनाइटेड किंगडम ने हैंडगन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और शिकार, शूटिंग या वध के लिए हथियारों की आपूर्ति सीमित कर दी है। भारत कुछ उन चुनिंदा देशों में है, जहां प्रति 100 व्यक्ति में केवल 5 के पास ही हथियार है। ❑❑

स्व–आधारित वैचारिक अधिष्ठान

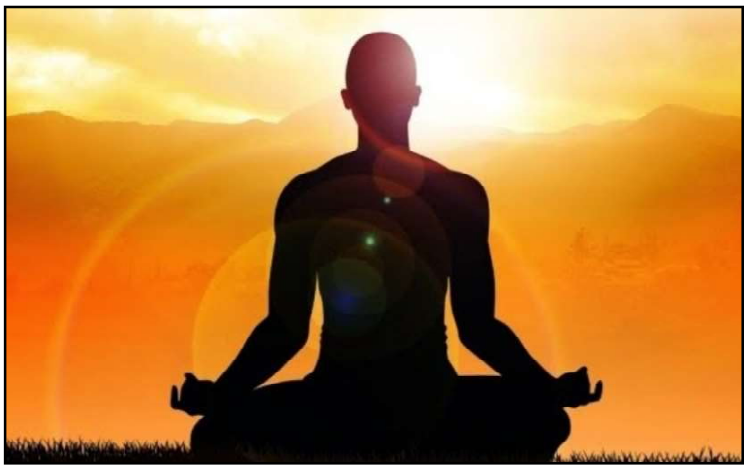

स्व–आधारित विषय पर चिंतन और लेखन एक लगातार वैचारिक मंथन की आवश्यकता को अभिभूत करता है। सर्वप्रथम तो 'स्व' को समझने की आवश्यकता है। हमारे यानि विश्व–ब्रह्मांड में और विशेषकर भारतवर्ष में इस 'स्व' के विषय में चिंतन और मनन होता आया है। 'स्व' के विराट और समग्र रूप में 'स्व' यानि अहम् की वह स्थिति जहां द्वैत न हो, यानि 'एकम सद विप्रा बहुदा वदंति' और इसी प्रकार अहम् ब्रह्मस्मि आदि तथा अन्य कई रूपों में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। इसी आधार पर अद्वैत तथा अखण्ड ब्रह्मांड का चिंतन तथा फिर पारस्परिक प्रेम–अहिंसा आदि स्वाभाविक धर्म के बारे में समाज निर्माण की प्रक्रिया तथा बहुत से दर्शन शास्त्रों का उल्लेख हमें मिलता है। मनुष्य–जाति की सभ्यता और संस्कृति का परिचय भी हमें उसकी सम्वेदनशीलता से ही मिलता है और इन्हीं तत्वों के अनुसार हम आपस में दया, करुणा तथा पारस्परिक सेवा भाव को मनुष्य–जाति का धर्म बताते हैं, जिसका अधिष्ठान अहिंसा और आपसी आत्मीयता और प्रेम है। इस प्रकार एक सार्वभौमिक सत्ता की विविधता और एकता की भी बात हमें समझ में आती तो है, किंतु व्यावहारिक जगत में अपने ही पूर्व के प्रारब्ध और प्राकृतिक गुण और स्वभाव के कारण हम उसे स्वीकार नहीं करते और यहीं से विवाद के विमर्शों का जन्म होने लगता है। पारस्परिक समरसता का संवाद तो होता है, परंतु व्यवहार में विवाद आ जाता है क्योंकि अलग–अलग व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता।

'स्व' का चिंतन और मनन करने से हमें स्वयं और समाज के प्रति स्वधर्म यानि अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है। 'स्व' का लक्ष्य स्वाधीन होना है अर्थात् बंधनों से मुक्ति।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

प्रकृति तीन गुणों से बनी है और इन तीन गुणों के आधार तथा अनुपात में अलग–अलग स्वभाव और फिर तदनुसार विचार और व्यवहार होने लगते हैं। एक व्यक्ति की विचारधारा का दूसरे की विचारधारा से टकराव प्रारंभ हो जाता है और यहां तक कि व्यक्ति के स्वयं के मन, बुद्धि और अहम् में भी टकराव होते रहता है। इस टकराव को कम करने और ख़त्म करने के लिये ही समाज का निर्माण होता है और सामाजिक नियम बनते हैं ताकि एक समुदाय में रहने वाले लोग पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपने जीवन–शैली में कुछ अनुशासन का पालन करते हुए अपनी जीविका चलाते हैं और फिर धीरे–धीरे उनमें विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है और सामाजिक नियम और आचरण एक विशेष धर्म या सम्प्रदाय का रूप लेने लगते हैं। समस्या तब होने लगती है जब एक सम्प्रदाय के विचार और व्यवहार में दूसरे संप्रदाय के साथ सामंजस्य में कमी आने लगती है। इसका कारण भौगोलिक दृष्टि से आवश्यकताओं और संसाधनों की असमानता भी हो सकती है, जिससे आर्थिक विषमता आने लगती है और सम्प्रदाय तथा समाज में वैषम्य और वैचारिक टकराव होने लगता है। यानि भौतिक कारणों से वैचारिक टकराव यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया सी लगाने लगती है और इसे सिर्फ़ भौतिक संसाधनों के सामाजिक न्याय के आधार पर वितरण की व्यवस्था के द्वारा कुछ समय के लिये तो मिटाया जा सकता है किंतु कुछ समय के बाद फिर से वैचारिक प्रभुता

और अहमता एक टकराव का विषय बन जाती है। अहम् और अस्मिता का तालमेल बिगड़ने लगता है, जिसका समाधान भौतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि 'स्व' के विस्तार से मानसिक बदलाव से ही संभव है।

'स्व' के व्यापक आधार पर हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन और संयम की आवश्यकता है। हमें स्वधर्म को समझने की आवश्यकता है। हमारे अव्यक्त चेतन को जगाकर इंद्रिय और मन में संयम के द्वारा अन्य को उस एक चेतन तत्व का अविभक्त तत्व समझकर उसके साथ समरसता का व्यवहार ज़रूरी है।

"श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्
स्वनुष्ठितात्"।
स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः।।
(गीता 3/35)

भगवान श्रीकृष्ण स्वधर्म पालन के सिद्धांत को समझते हुए अपने स्वयं के प्राकृतिक गुणों को ठीक से समझते हुए अपने कर्म को सुनिश्चित दिशा में ले जाना तथा शास्त्रों का अध्ययन एवं स्वाध्याय द्वारा शास्त्र विहित कर्म ही करना, शास्त्र–निषिद्ध कर्म नहीं करना, परहित को अपना ध्येय समझते हुए कर्म करना आदि ये कुछ ऐसे शाश्वत सत्य और शील के आधार तत्व हैं, जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान के मूल हैं। गीता के अनुसार स्वधर्म अगर किसी कारण से किसी प्रकार से किसी प्रकार की कमी से भी ग्रसित है, तब भी दूसरे के धर्म से श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म कष्ट देने वाला और भयावह है। हमारे वैदिक वांगमय में धर्म को कर्म और कर्तव्य बतलाया गया है। अतः इसका अर्थ पूजा पद्धति या उपासना पद्धति से नहीं जोड़ना चाहिये। एक शिक्षक का धर्म एक व्यवसायी या एक सिपाही से अलग हो सकता है। इसी आधार पर *"धर्मो रक्षति रक्षितः"* यानि धर्म उसी की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है। अतः आज के संदर्भ में स्वदेशी को अपनाना हमारा स्वधर्म है, और इस स्वधर्म के पालन से ही हम स्वावलंबी बन सकेंगे। स्वदेशी का समग्र रूप से सत्यता के साथ पालन ही स्वधर्म है, विदेशी संस्कृति के चकाचौंध में स्वदेशी वस्तुएं देखने में थोड़ी कम आकर्षक लगें या थोड़ी त्रुटियुक्त भी हो, तो उनका व्यवहार श्रेयस्कर है।

'स्व' का चिंतन और मनन करने से हमें स्वयं और समाज के प्रति स्वधर्म यानि अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है। 'स्व' का लक्ष्य स्वाधीन होना है अर्थात् बंधनों से मुक्ति। बंधन क्या है, शरीर निर्वाह से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का उपभोग और संग्रह। 'तेन त्यक्तेन भूँजीथा' का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम त्यागपूर्वक कम से कम वस्तुओं का उपभोग करें। त्याग किसके लिये, हमारे आस पास जो गरीब या दुर्बल व्यक्ति है उसके प्रति सहानुभूति और दया तथा करुणा का भाव यही हमारा स्वभाव होना चाहिये। हमारे स्वभाव में ज़्यादा उपभोग और संग्रह की इच्छा है तो उस पर बुद्धि और विवेक के द्वारा संयम की आवश्यकता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में पंच यज्ञ का प्रावधान है जिसके आधार पर देव यानि सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि आदि देवों को अर्पण, हमारे पूर्वज जो आज इस जगत में नहीं रहे उनके लिये तर्पण, पशु–पक्षी उनके लिये भी कुछ भोजन–सामग्री का त्याग आदि हमारे उपभोग की प्रवृत्ति के नियमन के लिये ज़रूरी हैं। ऐसा करने से हम अपनी इच्छाओं की गुलामी से बचेंगे और स्वाधीनता की प्रथम सीढ़ी पर पाँव रख सकेंगे। यह हमारा 'स्व' आधारित वैचारिक अधिष्ठान का प्रथम चरण होना चाहिये।

हमारे जीवन व्यवहार में सत्यता और शुचिता होनी चाहिये, संतोष होना चाहिये, हम व्यभिचारी न हों, हमारे आचरण में चोरी, बेमानी न हो, ये हमारे व्यावहारिक जीवन के स्तम्भ होने चाहिये. तभी हम सही माने में स्वाधीन ही सकेंगे, नहीं तो हम स्वयं की इच्छा के बंधन में रहकर उनकी गुलामी करेंगे। अर्थात् सरल भाषा में 'स्व' का तात्पर्य स्वाधीन, अपने आप से स्वाधीन और अपनी स्व आधारित चेतना के अनुसार विवेक पूर्वक जीवन शैली का निर्माण, यह स्व आधारित वैचारिक अधिस्ठान का दूसरा चरण। यानि अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानना और उसके अनुकूल आचरण करना ही हमारी स्वाधीनता का मूल है और यही हमारे स्वावलम्बन का भी मूल है। अगर हम अपनी अवश्क्ताओं को एक सीमा तक बांध कर रखेंगे तो स्वयं भी स्वावलंबी बनेंगे और अपने आस–पास के लोगों को भी अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा स्वावलंबी बनाने में मदद कर सकेंगे। सभी के साधन और बुद्धि विवेक एक जैसे नहीं हो सकते, इसी लिये पारस्परिक सहयोग, समरसता की आवश्यकता है जो हमारे भीतर के सदगुणों द्वारा सम्भव है। इसी स्वाधीन और स्वावलम्बन के आचरण का नाम स्वदेशी है। प्रथम आवश्यकता स्वयं के स्वभाव में परिवर्तन और संयम के आधार पर उपभोग और फिर दूसरे के हित को ध्यान में रखकर सत्य और शील का व्यवहार। इतना हो जाने से हम स्वाभाविक रूप से अपने नज़दीक के व्यक्ति द्वारा निर्मित व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे और यहीं से स्वदेशी भावना का निर्माण और उसका समवर्धन प्रारम्भ होता है। पहले स्वधर्म को समझना, फिर उसे आचरण में लाना और क्रमशः उस विचार का समाज में प्रचार करना, यह अगर सभी व्यक्ति करने लग जाएँगे तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी, विचारों में टकराव घटेगा, हिंसा की प्रवृत्ति घटेगी, संवाद बढ़ेगा, समाज में अच्छे विचार बनेंगे, नई ऊर्जा और सृजन शक्ति का विकाश होगा, शोषण रुकेगा, पर्यावरण सुदृढ़ होगा और वैश्विक शान्ति और समृद्धि का मार्ग प्रतिष्ठित होगा। ❑❑

घातक है विदेशों में पढ़ाई का क्रेज़

पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26.44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए। एसोसिएटेड चेम्बरर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया। वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डालर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रूपए रहा और रेडसियर स्टार्टेजी कन्स्लटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डालर यानि 7 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री बी. मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4.44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6.46 लाख थी, यानि 45 प्रतिशत की वृद्धि।

यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है।

विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि कई कारणों से चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये युवा पढ़ाई और रोजगार की तलाश में विदेशों को पलायन कर रहे हैं और इस कारण देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है, इससे देश के उद्योग–धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है।

देश के अनभिज्ञ युवा, जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस हेतु आगे आना होगा।

– स्वदेशी संवाद

इसके अलावा देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता–पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर इन युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज़ के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानि अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डालर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकटकारी स्थिति का कारण बनेगा।

नहीं है देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी

गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो–तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990–91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्याार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020–21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटेतौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्याार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15.51 लाख शिक्षक कार्यरत थे। देश में कई विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं और कई 'विश्वविद्यालय सम' यानि 'डीम्ड विश्वविद्यालय' हैं। देश में कई विश्वस्तरीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं।

जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है।

तो सवाल उठता है कि भारी भरकम राशि खर्च कर भारत के युवा विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश क्यों लेते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहां तक कि इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहां के स्थानीय लोग भारतीय एवं अन्य देशों से आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही हैं। देश से जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहां रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और उन्हें स्वदेश वापिस लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं।

विदेश जाने की क्रेज़ को थामने की जरूरत

चूंकि व्यक्तिगततौर पर विदेशों में जाने वाले युवा विद्यार्थी, पूर्व में विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से प्रभावित होकर विदेशों की ओर रूख कर रहे हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे कि आज कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में, जहां वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, वे शिक्षा संस्थान स्वयं के आस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपनी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं भारतीय और अन्य देशों के अति इच्छुक विद्यार्थियों से भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खुल रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है।

ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को इस हेतु वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विदेशों में जाकर अपने माता–पिता की गाढ़ी कमाई को यूं ही न गवा दें। गौरतलब है कि पिछले लगभग दो दशकों से भारत के कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेशों में, ख़ास तौर पर खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश में गए और वहां उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह–तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए।

इसी तर्ज पर देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस हेतु आगे आना होगा। ❑❑

भारत@2047:

भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकी

भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का अंश 17.6 प्रतिशत है, लेकिन विश्व के सकल रोग भार में भारत का अंश 21 प्रतिशत है। किसी भी राष्ट्र को तब तक वास्तव में विकसित नहीं माना जा सकता जब तक उसके नागरिक और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चिकित्सकीय रूप से उन्नत न हो। स्वास्थ्य किसी देश की प्रगति का आकलन करने के लिए एक पैरामीटर के रूप में कार्य करता है। अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर एक मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा, अपने नागरिकों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत ने पहले ही बड़ी संख्या में चिकित्सा उपकरणों का निर्माण और स्वदेशी कोविड–19 टीके विकसित करके आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रति यह प्रतिबद्धता स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने और खुद को एक विश्वसनीय वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाती है। चिकित्सा प्रगति को प्राथमिकता देकर, भारत का लक्ष्य एक स्थायी और उन्नत स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो अपने नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है और देश की समग्र प्रगति और कल्याण में योगदान देता है।

अगले दो दशकों में, जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और चिकित्सा विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। वैश्विक स्तर पर पर उम्र बढ़ने वाली आबादी के कारण बुजुर्ग देखभाल और उम्र से संबंधित बीमारियों के उपचार की मांग में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत और पुरानी बीमारियों की व्यापकता, आर्थिक चुनौतियां पेश कर सकती है।

उन्नत प्रौद्योगिकी, आर्थिक व्यवहार्यता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एकीकृत करने वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देकर, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां चिकित्सा प्रगति लोगों और राष्ट्रों की भलाई में सुधार करेगी।

– डॉ. जया शर्मा

वैश्विक स्वास्थ्य खतरों का मुकाबला करने के लिए दुनिया को एकजूट आने की आवश्यकता होगी। आर्थिक संसाधनों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि भूमिका निभाएगा। वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर सामूहिक प्रतिक्रिया साझा प्रतिबद्धता और वित्तीय निवेश पर निर्भर करेगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी की प्रगति इसकी सामर्थ्य और आर्थिक व्यवहार्यता दोनों पर निर्भर करेगी। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा विज्ञान के भविष्य को आकार देने में जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए, ये कारक आपस में जुड़े होंगे। तेजी से तकनीकी प्रगति से चिह्नित युग में, व्यवधान की संभावना सभी उद्योगों में प्रतिध्वनित होती है, लेकिन कुछ ही चिकित्सा क्षेत्र के समान गहराई से प्रभावित होते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, डेटा–संचालित ज्ञान और नवाचार की असीमित खोज के अंतर्संबंध ने एक परिवर्तनकारी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है, जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग को नया आकार देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीनोमिक्स से लेकर टेलीमेडिसिन और पहनने योग्य उपकरणों तक, ये विघटनकारी प्रौद्योगिकियां चिकित्सा जगत में क्रांति लाने, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण की सीमाओं को पार करने और रोगियों और चिकित्सकों दोनों को अभूतपूर्व क्षमताओं के साथ सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं।

सर्जिकल प्रक्रियाओं का भविष्य

भविष्य में, सर्जिकल प्रक्रियाओं को संचालित करने वाले रोबोट की अवधारणा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल के एक उल्लेखनीय संलयन का प्रतीक होगी। रोबोटिक सर्जरी एक नए

युग की शुरुआत करेगी, जहां मानव सर्जन सटीकता, निपुणता और समग्र सर्जिकल परिणामों को बढ़ाने के लिए परिष्कृत रोबोटिक प्रणालियों के साथ सहयोग करेंगे। ये सर्जिकल रोबोट न्यूनतम आक्रामक प्रक्रियाओं, सर्जिकल आघात को कम करने, बेहतर दृश्यता और रोगी के ठीक होने के समय में सुधार की क्षमता प्रदान करेंगे।

रोबोटिक सर्जरी के प्रमुख लाभों में से एक मानव हाथों की सीमाओं को दूर करने की इसकी क्षमता होगी। रोबोटिक साधन अत्यधिक व्यक्त उपकरणों से सुसज्जित होंगे जो पारंपरिक लेप्रोस्कोपिक उपकरणों की तुलना में गति और सटीकता बढ़ाएंगे। सर्जन इन रोबोटिक साधन को एक कंसोल से नियंत्रित करेंगे, उपकरणों को अधिक स्थिरता और सटीकता के साथ संचालित करेंगे, और इनके साथ एक 3–डी हाई–डेफिनिशन कैमरा सिस्टम सर्जिकल साइट का एक विस्तृत, गहन दृश्य प्रदान करेगा। उन्नत प्रौद्योगिकी और मानव विशेषज्ञता का यह संयोजन जटिल शल्य प्रक्रियाओं को अभूतपूर्व सटीकता के साथ निष्पादित करने की सुविधा देगा।

इसके अलावा, रोबोटिक सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम को शामिल करने की क्षमता होगी जो जटिल प्रक्रियाओं के दौरान सर्जन की सहायता कर सकती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में रोगी डेटा का विश्लेषण करेगा, सर्जिकल निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमानित विश्लेषण प्रदान करेगा। मशीन लर्निंग की क्षमताओं के साथ मानव बुद्धि का यह संलयन सर्जिकल योजना को उन्नत करेगा, इंट्राऑपरेटिव मार्गदर्शन में सुधार करेगा और पोस्ट–ऑपरेटिव देखभाल को अनुकूलित करेगा।

वैसे सर्जरी में रोबोट के एकीकरण से अपार संभावनाएं विकसित होंगी, लेकिन इस प्रगति के साथ आने वाली चुनौतियों और नैतिकता की चुनौतियों को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण होगा। सुरक्षा, विश्वसनीयता और रोबोटिक प्रक्रियाओं में सर्जनों के कठोर प्रशिक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता महत्वपूर्ण पहलू बने रहेंगे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे–जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है और रोबोटिक प्रणालियों की क्षमताओं का विस्तार हो रहा है, सर्जिकल हस्तक्षेपों में जो संभव है उसकी सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जाएगा।

डायग्नोस्टिक परीक्षण में नैनोटेक्नोलॉजी का भविष्य

नैनोटेक्नोलॉजी, नैनोस्केल (एक मीटर का एक अरबवां हिस्सा) पर पदार्थ में हेरफेर करने का विज्ञान, पारंपरिक निदान में क्रांति लाने की जबरदस्त क्षमता रखेगा। इस पैमाने पर सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय गुणों का उपयोग करके, नैनोटेक्नोलॉजी बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम के नए तरीके खोलेगी। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर इसका प्रभाव कई मायनों में परिवर्तनकारी होगा।

उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक जहां नैनोटेक्नोलॉजी गहरा अंतर लाएगी, वह है दवा वितरण। नैनोकणों को दवाओं को समाहित करने के लिए इंजीनियर किया जाएगा, जिससे शरीर के भीतर चिकित्सीय पदार्थों को सटीक लक्ष्यीकरण और नियंत्रित रिलीज की अनुमति मिलेगी। ये नैनोकण जैविक बाधाओं के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम होंगे, दवाओं को सीधे विशिष्ट कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाएंगे, और यहां तक घ्कि पीएच या एंजाइम स्तर जैसे विशिष्ट उत्तेजनाओं के जवाब में दवाएं भी जारी करेंगे। यह लक्षित दवा वितरण दृष्टिकोण दुष्प्रभावों को कम करते हुए और आवश्यक खुराक को कम करते हुए उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।

नैनोटेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को भी सक्षम बनाएगी। नैनोसेंसर और नैनोडिवाइस को अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील स्तर पर विशिष्ट बायोमार्कर या रोगजनकों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इन छोटे उपकरणों को पहनने योग्य सेंसर, प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों में शामिल किया जाएगा, या यहां तक कि देखभाल बिंदु परीक्षण में भी उपयोग किया जाएगा। उच्च सटीकता और गति के साथ प्रारंभिक चरण में बीमारियों का पता लगाने की क्षमता समय पर हस्तक्षेप और रोगी के परिणामों में सुधार की अनुमति देगी। जबकि पारंपरिक चिकित्सा में नैनोटेक्नोलॉजी की क्षमता विशाल होगी, बायोकम्पैटिबिलिटी, विषाक्तता और नैनोमटेरियल्स की दीर्घकालिक सुरक्षा जैसी चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण होगा। नैनो–प्रौद्योगिकी–आधारित चिकित्सा हस्तक्षेपों के जिम्मेदार विकास और तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अनुसंधान और विनियमन महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष: इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा विज्ञान का भविष्य वादों और चुनौतियों दोनों से चिह्नित होता है ऊपर उल्लिखित प्रौद्योगिकियों के अलावा, जीनोमिक्स इंजीनियरिंग, जीनोम संपादन, आणविक चिकित्सा, कुछ नाम स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को परिभाषित करेंगे। ये अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा लाए गए संभावित योगदान के साथ, निदान और चिकित्सीय उपचार के पारंपरिक तरीकों को बदलने के लिए तैयार हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी, आर्थिक व्यवहार्यता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एकीकृत करने वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देकर, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां चिकित्सा प्रगति लोगों और राष्ट्रों की भलाई में सुधार करेगी। यह मार्ग न केवल प्रगति का प्रतीक है बल्कि सभी के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए साझी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। ❑❑

आतंक के रक्तबीज हमास के इज़राएल पर आक्रमण की पृष्ठभूमि

जब 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से दक्षिणी इज़राइल में रॉकेट हमले के साथ हमास का बर्बर और निर्मम हमला शुरू हुआ तब विश्व स्तब्ध रह गया और हमास के विरुद्ध सम्पूर्ण विश्व में दुख, क्रोध और आलोचना व्याप्त हो गयी। इसके साथ ही, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए, गाज़ा पट्टी की सीमा के पार सशस्त्र ड्रोन, मोटरबाइकों पर लड़ाके और पैराग्लाइडर भेजे। इज़रायली नागरिक जो शबात (इज़रायल के उत्सव के दिन) के दौरान आनंदमय थे – अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमास के घातक, पूर्व नियोजित और विभिन्न दिशाओं से ऑपरेशन इज़राइल का सबसे भयानक दुःस्वप्न था।

इज़रायली विश्लेषकों ने इस हमले को 1948 (जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी) के बाद से यहूदी राज्य के क्षेत्र के अंदर सबसे भयानक हमला बताया है। इज़राएल में कम से कम 600 लोग मारे गए थे और हमास ने 100 लोगों को बंधक बना लिया था। इज़राइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 का संघर्ष कई दशकों से चल रहे इज़राइली–फिलिस्तीनी संघर्ष में सबसे अतिरेक वृद्धि का प्रतीक है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमास उत्तर कोरियाई हथियारों का भी प्रयोग कर रहा है।

आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हमास, आईएसआईएस, अल कायदा, तालिबान, लश्कर–ए–तैयबा, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, टीटीपी ने कई दशकों से आतंक और खून–खराबा फैला रखा है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए विश्व को एकजुट होना होगा।

– विनोद जौहरी

इस आक्रमण को "तीसरा इंतिफ़ादा" (अरबी शब्द का अर्थ विद्रोह) के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है। पहला इंतिफ़ादा 1987 से 1993 तक और दूसरा 2000–2005 तक चला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़राइल पर हमास के हमले की तुलना भारत में मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले से की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन सहित यूरोपीय देशों ने हमास की निंदा की, जबकि रूस, तुर्की, कुछ मध्य पूर्व देशों और चीन ने इज़राइल और अमेरिका को दोषी ठहराया है। इसके विपरीत, मिस्र और जॉर्डन ने अपने देशों में फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। ऐसी आशंकाएं हैं कि यह लड़ाई

तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकती है क्योंकि फरवरी 2022 से ही रूस–यूक्रेन के बीच लंबे समय तक युद्ध की आग भड़क चुकी है।

अब मरने वालों की कुल संख्या 7,500 से अधिक हो गई है। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार है और सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। इज़राइल और हमास की वर्तमान शत्रुता अब्राहम समझौते और सऊदी अरब और इज़राइल के बीच समझौतों के प्रयासों की प्रतिक्रिया प्रतीत होती है, जिसमें वह मध्य पूर्व में सदियों पुरानी शत्रुता समाप्त करके सामान्य स्थिति चाहते हैं।

गाजा भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो इज़राइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित है, लेकिन मिस्र के साथ इसकी एक छोटी दक्षिणी सीमा है। केवल 41 किमी (25 मील) लंबा और 10 किमी चौड़ा, इसमें 20 लाख से अधिक निवासी हैं और यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। गाजा पर इस्लामी कट्टरपंथी समूह हमास का शासन है जो इज़राइल को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है और ब्रिटेन और कई अन्य देशों द्वारा यह एक आतंकवादी समूह के रूप में परिभाषित है।

हमास ने 2006 में फिलिस्तीनियों का अंतिम चुनाव जीता था, और अगले वर्ष वेस्ट बैंक स्थित राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रतिद्वंद्वी फतह आंदोलन को पदच्युत कर गाजा पर नियंत्रण कर लिया था। तब से, गाजा में आतंकवादियों ने इज़राइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं, जिसमें मिस्र के साथ मिलकर हमास ने इजरायली शहरों की ओर रॉकेटों की अंधाधुंध गोलीबारी की है।

7 अक्टूबर 2023 के हमलों में वर्ष 1973 के युद्ध की प्रतिध्वनि है जब मिस्र और सीरिया ने यहूदी धर्म के सबसे पवित्र दिन, योम किप्पुर पर सिनाई और गोलान हाइट्स में अरब आक्रमण का नेतृत्व करके इज़राइल पर हमले किए थे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमास ने उस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के करीब अपना हमला शुरू किया। लेकिन शनिवार का हमला इजराइल के अंदर हुआ और नागरिकों को निशाना बनाया गया, जबकि 1973 में सिनाई और गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे में थे। 2007 में गाजा पर कब्ज़ा करने के बाद से हमास के साथ कम से कम चार युद्ध लड़ने के बावजूद, इज़राइल ने स्पष्ट रूप से आतंकवादियों की क्षमता को कम करके आंका है। इसके पूर्व का संघर्ष 2021 में हुआ था जब हमास ने इज़राइल में हजारों रॉकेटों से बमबारी की, जिससे इज़राइली सुरक्षा अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। इज़राइल ने गाजा पर हवाई हमलों और तोपखाने से हमला करके जवाब दिया और कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी।

ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पहले ही हमास के साथ आक्रमण में शामिल हो चुका है और उसके पास हमास की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और अधिक परिष्कृत रॉकेट और मिसाइल शस्त्रागार है। संघर्ष में इसकी भागीदारी ने इज़राइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली को खतरे में डाल दिया है, जो इसके कस्बों और शहरों की रक्षा करती है। हिजबुल्लाह ने 2006 में एक महीने तक चले संघर्ष के दौरान इजराइल को गहरे जख्म दिये थे और राष्ट्रपति बशर अल–असद का समर्थन करने के लिए सीरिया के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप करने के बाद उसे युद्ध के मैदान का अनुभव प्राप्त हुआ है।

इन घटनाओं से इजरायल को यह भी भय है कि ईरान, जो हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) का समर्थन करता है, गाजा में एक और आतंकवादी फिलिस्तीनी समूह है, जो आग भड़काने का फैसला कर सकता है। इस बीच, वेस्ट बैंक भी तनावग्रस्त है क्योंकि यह 2005 में समाप्त हुए दूसरे इंतिफादा या फिलिस्तीनी विद्रोह के बाद से हिंसा के सबसे खराब काल चक्र को झेल रहा है। हाल के वर्षों में शायद ही कभी स्थिति इतनी ज्वलनशील दिखाई दी हो। युद्ध ने पहले ही लेबनान और सीरिया को अपनी चपेट में ले लिया है।

पृष्ठभूमि

1. इजरायल–फ़िलिस्तीनी संघर्ष उन्नीसवीं सदी के अंत से चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में मध्य पूर्व के उस हिस्से पर शासन करने वाले ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। भूमि पर यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक, साथ ही अन्य छोटे जातीय समूह रहते थे। दोनों लोगों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए अलग देश स्थापित किया। इसकी परिणति 1917 की बाल्फोर घोषणा से हुई थी, जो तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा ब्रिटेन के यहूदी समुदाय को दी गई एक प्रतिबद्धता थी। यह घोषणा फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश में निहित थी और 1922 में नव–निर्मित राष्ट्र संघ – संयुक्त राष्ट्र के अग्रदूत – द्वारा इसका समर्थन किया गया था। यहूदियों के लिए, फ़िलिस्तीन उनका पैतृक स्थान था, लेकिन फ़िलिस्तीनी अरबों ने भी भूमि पर दावा किया और इस कदम का विरोध किया।

2. वर्ष 1920 और 1940 के दशक के बीच, वहां पहुंचने वाले यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई, कई लोग यूरोप में उत्पीड़न विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी नरसंहार से भागकर वहाँ गए। यहूदियों और अरबों के बीच और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसा भी बढ़ गई। 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग–अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, साथ ही यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय

शहर बना दिया। उस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और कभी लागू नहीं किया गया।

3. 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प (रेसोल्यूशन) 181 को पारित किया, जिसे विभाजन योजना के रूप में जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग की गई थी। 14 मई, 1948 को, इज़राइल राज्य का निर्माण हुआ, जिससे पहला अरब–इजरायल युद्ध छिड़ गया। 1949 में इज़राइल की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 750,000 फ़िलिस्तीनी विस्थापित हो गए, और क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया– इज़राइल राज्य, वेस्ट बैंक (जॉर्डन नदी का), और गाजा पट्टी।

4. 1948 में, समस्या को हल करने में असमर्थ, ब्रिटेन पीछे हट गया और यहूदी नेताओं ने इज़राइल राज्य के निर्माण की घोषणा की। इसका उद्देश्य उत्पीड़न से भाग रहे यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होना और साथ ही यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि होना था। यहूदी और अरब मिलिशिया के बीच लड़ाई महीनों से तेज थी, और इज़राइल द्वारा राज्य का दर्जा घोषित करने के अगले दिन, पांच अरब देशों ने हमला किया। सैकड़ों–हजारों फिलिस्तीनी भाग गए या उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे वे अल नकबा या "तबाही" कहते हैं। अगले वर्ष युद्ध विराम के रूप में लड़ाई समाप्त होने तक, इज़राइल ने अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया।

5. जॉर्डन ने उस भूमि पर कब्ज़ा कर लिया जिसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और मिस्र ने गाजा पर कब्ज़ा कर लिया। यरूशलेम को पश्चिम में इजरायली सेनाओं और पूर्व में जॉर्डन की सेनाओं के बीच विभाजित किया गया था। चूँकि कभी कोई शांति समझौता नहीं हुआ था इसलिए अगले दशकों में और अधिक युद्ध और लड़ाइयाँ हुईं।

इज़राइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया है। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से निकालने के लिए 'ऑपरेशन अजय' शुरू किया है।

6. वर्ष 1967 में युद्ध में, इज़राइल ने पूर्वी येरुशलम और वेस्ट बैंक के साथ–साथ अधिकांश सीरियाई गोलान हाइट्स, गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गाजा और वेस्ट बैंक के साथ–साथ पड़ोसी जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में रहते हैं। न तो उन्हें और न ही उनके वंशजों को इज़राइल ने अपने घरों में लौटने की अनुमति दी है – इज़राइल का कहना है कि इससे देश पर दबाव पड़ेगा और एक यहूदी राज्य के रूप में इसके अस्तित्व को खतरा होगा।

7. वर्ष 1948–49 के युद्ध के बाद गाजा पर 19 साल तक मिस्र का कब्जा रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "आतंकवादी हमले" पर आश्चर्य व्यक्त किया और "इज़राइल के साथ एकजुटता" व्यक्त की। "इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं,'' प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा। हमारे दूतावास की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार, इज़राइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं: जिनमें इज़राइली बुजुर्गों द्वारा नियोजित देखभालकर्ता, हीरा व्यापारी, आईटी पेशेवर और छात्र शामिल हैं।

भारत सहित कई देशों ने मिस्र की सीमाओं के माध्यम से फिलिस्तीन को मानवीय सहायता देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपत्री से भी मानवीय सहायता के लिए वार्ता की है।

इज़राइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया है। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से निकालने के लिए 'ऑपरेशन अजय' शुरू किया है।

इस ऑपरेशन के लिए विशेष चार्टर उड़ानें और आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ऑपरेशन की निगरानी के लिए दिल्ली में 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए तेल अवीव और रामल्लाह में अलग–अलग आपातकालीन हेल्पलाइन चालू हैं।

आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हमास, आईएसआईएस, अल कायदा, तालिबान, लश्कर–ए–तैयबा, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, टीटीपी ने कई दशकों से आतंक और खून–खराबा फैला रखा है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए विश्व को एकजुट होना होगा। ❑❑

विनोद जौहरी, पूर्व अपर आयकर आयुक्त

वैश्विक स्तर पर नया आकार ले रहा है भारत का सांस्कृतिक वैभव

भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हुए भारत के आर्थिक विकास को देखकर अब विकसित देश भी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं ताकि वे अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल कर सकें। कुल मिलाकर अब भारतीय आर्थिक दर्शन ही पूरे विश्व को बचा सकता है, क्योंकि वह कर्म आधारित है और एकात्म मानवता पर केंद्रित है।

–प्रहलाद सबनानी

भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और परम्पराएं विश्व में सबसे अधिक प्राचीन मानी जाती है। भारतीय संस्कृति को विश्व की अन्य संस्कृतियों की जननी भी माना गया है। भारत की संस्कृति और सभ्यता आदि काल से ही अपने परम्परागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। भारत में गीत संगीत, नाटक परम्परा, लोक परम्परा, धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, चित्रकारी और लेखन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। इसे संजोने, संवारने और निखारने का महती प्रयास हाल के समय में बहुत मजबूती के साथ किया जा रहा है। विशेष रूप से पिछले एक दशक में भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं जिससे न केवल विश्व के लोगों को देश के माटी की सौंधी खुशबू मिली है बल्कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को जानने एवं समझने का प्रयास भी कर रही है। भारत का अतीत वर्तमान से भी सुंदर एवं प्रभावशाली रहा है।

भारत ने राजनैतिक स्वतंत्रता 75 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली थी, परंतु भारत की सनातन संस्कृति आदि काल से चली आ रही है। भारत को 'सोने की चिड़िया' के रूप में जाना जाता रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति का लोहा पूरे विश्व ने माना है। धर्म, दर्शन, विरासत, तीज, त्यौहार, जायका और अनेकता में एकता के दर्शन करने को पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती रही है। भारत को देव भूमि भी कहा गया है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है और यह समर्पण की भूमि है।

भारत आदि काल से ही एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास बताया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में विरासत पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और भारत में आर्थिक विकास के साथ ही सांस्कृतिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। जिसके चलते अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। बल्कि अब तो अन्य कई देश, विकसित देशों सहित, भी अपने आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्याओं के हल हेतु एवं अपने आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से भारतीय सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

हाल ही के समय में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संवारने और उसकी संवृद्धि के लिए विशेष रूप से पिछले दशक के दौरान अथक प्रयास किए गए हैं। हजारों वर्षों की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि कितने ही झंझावात क्यों न आए परंतु भारतीय सनातन संस्कृति अटूट रही। हालांकि कुछ देशों, जैसे ग्रीक, यूनान, ईरान आदि, की सभ्यताएं समूल नष्ट हो गईं। भारत में अभी हाल ही में आजादी के 75 वर्षों के बाद अमृत काल मनाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को प्रारम्भ हुई। जिसे आजादी की 75 वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की गिनती शुरू की थी जो उत्सवों के साथ निरंतर गतिमान रही। इस बीच उत्सवों की लम्बी

भारत ने हाल ही के वर्षों में अपनी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने एवं अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने में जो सफलता पाई है वह मुख्य रूप से भारत की सनातन संस्कृति एवं परम्पराओं का पालन करते हुए ही प्राप्त की जा सकी है। इसके ठीक विपरीत विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद से विश्व के कई विकसित देश अभी तक कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

श्रृंखला चली और 15 अगस्त 2023 तक यह यात्रा निर्बाध गति से चलती रही। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 166,000 से अधिक कार्यक्रम देश और दुनिया में आयोजित किए गए। जिसमें हर घर तिरंगा, वन्दे भारतम, कलांजलि जैसे कई बड़े कार्यक्रम भी शामिल रहे।

अमृत महोत्सव के पांच स्तम्भ हैं (स्वतंत्रता संग्राम/75, विचार/75, समाधान/75, कार्य/75, उपलब्धियां/75) जनभागीदारी से मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव, देश की इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक प्रयास है और इसके साथ ही अगले 25 वर्षों के लिए संकल्पों की रूपरेखा भी रखी जा रही है।

भारतीय सनातन संस्कृति ने न केवल भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है बल्कि पूरे विश्व को ही भारत के साथ जोड़ा है। अब तो भारत में 'एक भारत – श्रेष्ठ भारत' के रूप में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा है। भारत ने जी–20 समूह के देशों की अपनी अध्यक्षता के दौरान कई अतुलनीय कार्य किए है। पिछले लगभग एक वर्ष के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्य देशों की 200 से अधिक बैठकों का भारत के विभिन्न शहरों में आयोजन कर भारत ने पूरी दुनिया के समस्त देशों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत ने पूरी दुनिया को ही अपनी महान गौरवशाली सनातन संस्कृति, वैभवशाली विरासत, आध्यात्मिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, आदि का परिचय देने में सफलता हासिल की है।

भारत ने हाल ही के वर्षों में अपनी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने एवं अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने में जो सफलता पाई है वह मुख्य रूप से भारत की सनातन संस्कृति एवं परम्पराओं का पालन करते हुए ही प्राप्त की जा सकी है। इसके ठीक विपरीत विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद से विश्व के कई विकसित देश अभी तक कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियों के पालन से पश्चिमी देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। विकसित देशों में आज परिवार की प्रधानता एक तरह से समाप्त हो चुकी है। इस संदर्भ में यहां विशेष रूप से अमेरिका की स्थिति का उदाहरण दिया जा सकता है। अमेरिका में आज सामाजिक तानाबाना छिन्न भिन्न हो चुका है। दंपतियों में तलाक की दर बहुत अधिक हो गई है जिसके चलते बच्चे केवल अपनी मां के पास रह जाते हैं एवं बड़ी संख्या में बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं है।

विकसित देशों में पारिवारिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने के कारण बुजुर्गों को सरकार की मदद पर निर्भर रहना होता है। अतः इन देशों की सरकारों को सामाजिक सुविधाओं पर भारी भरकम राशि खर्च करनी होती है। कई विकसित देशों में तो बुजुर्गों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसके चलते इन देशों को अपने बजट का बहुत बड़ा भाग सामाजिक सुविधाओं पर खर्च करना पड़ रहा है। फ्रांस अपने कुल बजट का 31 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुविधाओं पर खर्च कर रहा है, इसी प्रकार इटली 28 प्रतिशत, जर्मनी 26 प्रतिशत एवं अमेरिका 19 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुविधाओं पर खर्च कर रहा है। सामाजिक सुविधाओं पर भारी भरकम खर्च के कारण इन देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है एवं इन देशों में प्रति व्यक्ति औसत ऋण बहुत अधिक हो गए हैं। अमेरिका में तो कुल सकल घरेलू उत्पाद का 136 प्रतिशत कर्ज लिया जा चुका है। आज ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु भी कुछ देशों को कर्ज लेना पड़ता है।

पश्चिमी दर्शन की विचारधारा के ठीक विपरीत, भारतीय संस्कृति के अनुसार, व्यक्तिवाद के ऊपर परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि को क्रमशः माना गया है। संयुक्त परिवार के प्रचलन के कारण बुजुर्गों की देखभाल परिवार में ही होती है एवं सरकार के बजट पर इस संदर्भ में बहुत अधिक बोझ नहीं आता है। भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हुए भारत के आर्थिक विकास को देखकर अब विकसित देश भी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं ताकि वे अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल कर सकें। कुल मिलाकर अब भारतीय आर्थिक दर्शन ही पूरे विश्व को बचा सकता है, क्योंकि वह कर्म आधारित है और एकात्म मानवता पर केंद्रित है। ❑❑

किसान की जीवन निर्वाह आय यकीनी बनाएं

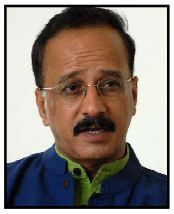

ऐतिहासिक रूप से लालची वैश्विक मूल्य शृंखला द्वारा छोटे भू-मालिकों, किसानों और पशु पालकों को अधिकारपूर्ण देय से वंचित रखा गया। केवल ईयू में ही नहीं बल्कि इस तरह के निर्देश का भारत जैसे देशों और बाकी विकासशील विश्व में भी अनुकरण किया जाना चाहिये। यह उस आय असमानता की खाई को पाटने में मददगार होगा जिससे दुनिया जूझ रही है और नहीं जानती कि इससे बाहर आने की राह क्या है।

– देविंदर शर्मा

किसानों के लिए जीवन निर्वाह आय की विभिन्न परिभाषाएं दी जाती रही हैं। इसको लेकर एक परिभाषा 1.8 मिलियन से अधिक किसानों के सहकार वाले वैश्विक आंदोलन फेयरट्रेड इंटरनेशनल ने भी दी है जिसके मुताबिक, घर के सभी सदस्यों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर वहन करने के लिए पर्याप्त आय– जिसमें पौष्टिक आहार, स्वच्छ पानी, ठीक–ठाक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य मूलभूत ज़रूरतों के साथ ही आपातकालीन स्थिति और बचत के लिए थोड़ा अतिरिक्त – उसके बाद जब एक बार कृषि लागत कवर हो जाये।'

कृषि विशेषज्ञ लगातार उस आर्थिक नुकसान की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं, जिसे भारतीय किसान झेल रहे हैं। किसानों को जीवन निर्वाह योग्य आमदन देने में आनाकानी ने कृषि संकट को बढ़ावा दिया है। दशकों से, हालांकि कृषि पैदावार में आशातीत वृद्धि हुई है लेकिन किसान की आय में सतत गिरावट जारी रही है। कई तरह से, यह कहना गलत नहीं होगा कि पैदावार में वृद्धि कृषक परिवारों की असल आमदन में औसत गिरावट की विपरीत समानुपातिक रही है।

साल 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के 17 राज्यों में, यानी तकरीबन आधे देश में किसानों की औसत आमदन मात्र 20,000 रुपये यानी 241 डॉलर प्रति वर्ष थी। इसका अर्थ है कि एक औसत किसान परिवार 1,700 रुपये यानी 21 डॉलर प्रति माह से कम में गुजर–बसर कर रहा था। यदि आप गांव में रहते हैं तो यह आय एक गाय पालने के लिए भी काफी नहीं है। ऐसी हास्यास्पद आय के साथ, किसान जिस दुख और अभाव की स्थिति में रहते हैं उसकी यकीनी तौर पर कल्पना की जा सकती है।

यह दयनीय आय स्तर आधे देश में रह रहे किसानों के लिए है। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर भी तस्वीर इतनी ही अपमानजनक है। कृषक परिवारों के लिए सिचुएशनल एसेसमेंट सर्वे 2019 के मुताबिक, किसान परिवार की सभी स्रोतों से औसत मासिक आय मात्र 10218 रुपये यानी 123 डॉलर बनती है। यह मानते हुए कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 50 फीसदी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर खेती में कार्यरत है, किसानों की दुर्दशा के पीछे मौजूद प्राथमिक वजह साफ तौर पर समझे जाने योग्य है।

वैश्विक स्तर पर भी, खेती का परिदृश्य इतना ही निराशाजनक है। यदि कृषि में बड़े पैमाने पर घरेलू समर्थन जो 2019–21 में सार्वजनिक बजट से भुगतान किया गया, 500 बिलियन डॉलर वापस ले लिया गया, तो विकसित देशों में खेती में जो कुछ भी बाकी है, उसका पतन निश्चित है। सरल शब्दों में कहें तो खेती करने वाली आबादी को लगातार वेंटिलेटर पर रखने का निरंतर प्रयास ही किसानों को जीवित रखता है, और किसी तरह से सभी रुकावटों के खिलाफ संघर्ष करने का बंदोबस्त करता है।

दुनिया के सामने आ रहा खेती से यह पलायन एक आर्थिक षडयंत्र का परिणाम है जिसने जानबूझकर खेती को गरीब बनाए रखा है। अन्य शब्दों में, विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी, यह आर्थिक डिजाइन है जिसने कृषक परिवारों को जीवन निर्वाह योग्य आय से वंचित कर दिया है, जिससे कृषि के पराभव को और बदतर कर दिया है। इस अहम मोड़ पर, फेयर ट्रेड, सॉलिडेरिडाड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ऑक्सफैम और माइटी अर्थ सहित 70

अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के एक ग्रुप को यूरोपीय संघ के कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस निर्देश (सीएसडीडीडी) में संशोधन की मांग करते हुए देखना बहुत खुशी की बात है जो प्रस्ताव में जीवन निर्वाह आमदनी और खरी खरीद प्रथाओं को शामिल करने के लिए है। 'हम सीएसडीडीडी और कंपनियों की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मानव अधिकारों और पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने के इसके लक्ष्य का स्वागत करते हैं। हालांकि, सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए, इसे अधिकार धारकों के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, खास तौर पर उनके जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सबसे कमजोर हैं।'

हालांकि यूरोपियन संसद ने पहले ही जीवन निर्वाह आय का संदर्भ (अनुलग्नक का भाग 1, उपशीर्षक 1, बिंदु 7) शामिल कर लिया है जिसमें कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थितियों का आनंद लेने का अधिकार, जिसमें सभ्य जिंदगी जीने के योग्य पारिश्रमिक भी शामिल है। सीएसओ की संयुक्त याचिका में 'स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और छोटे किसानों के लिए जीवन निर्वाह आय का अधिकार दोनों शामिल हैं' जिसमें गुजारे योग्य आय का स्पष्ट संदर्भ मांगा गया है ताकि छोटे भूमालिक और अन्य कमजोर वर्ग वास्तव में लाभ उठा सकें।

यह जानते हुए कि छोटे भूमालिक दुनिया की कुल खाद्य आपूर्ति का एक तिहाई हिस्सा पैदा करते हैं, और मूल निवासी एवं स्थानीय समुदाय वनों के करीब 1 बिलियन हेक्टेयर का प्रबंधन करते हैं, उनकी गुजारे लायक आजीविका सुरक्षा यकीनी बनाना महत्वपूर्ण है। ये समुदाय समाज के निचले पायदान पर रहते हैं। गरीबी से पार पाने को इन संवेदनशील समुदायों के लिए निर्वाह योग्य आय के साथ गुजारे योग्य पारिश्रमिक सुनिश्चित करना जरूरी है। जबकि जी–20 का प्रयास ग्लोबल वेल्यू श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करना है लेकिन इन कंपनियों को आधारभूत कच्चे माल के उत्पादकों के लिए आय सुरक्षा प्रदान करने का स्पष्ट निर्देश शामिल करना कभी किसी नीति निर्देशक का हिस्सा नहीं रहा है।

यह सर्वविदित है कि कैसे कुछेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में शक्ति केंद्रीकृत होने का परिणाम अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में सामने है जिसने एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में लाखों छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित किया।

कॉफी का मामला ही लें, जो 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, प्रतिदिन 3 अरब कप गटके जाते हैं, इसके बावजूद अधिकतर कॉफी बीन उत्पादक रोजाना 2.15 डॉलर में घोर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं। केवल कॉफी के लिए ही नहीं, बल्कि यह बात उन सभी कृषि पदार्थों के लिए है जिनका वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है। जबकि मूल्य श्रृंखलाओं का ऊपरी वर्ग जमकर लाभ कमाता है वहीं श्रृंखला के निम्नतम तल पर मौजूद गरीब उत्पादकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में वेल्यू चेन का जो हिस्सा कच्चे माल उत्पादकों के पास जाता है वह उत्पादन लागत को भी पूरी नहीं करता है।

भारत में डेयरी को–आपरेटिव्स के अनुभव से सीखा जा सकता है, जिसमें डेयरी किसान को अंतिम उपभोक्ता कीमत का 80 फीसदी प्राप्त होता है। अब यह आकलन करने का समय आ गया है कि ग्लोबल वेल्यू चेन के कारोबार के कितने फीसदी को जीवन निर्वाह आय के रूप में वर्गीकृत किया जाये। यह तथ्य कि उपभोक्ता कीमत का डेयरी किसान को मिलने वाला हिस्सा इतना ज्यादा है फिर भी निजी क्षेत्र समेत भारत में मिल्क प्लांट घाटे में नहीं हैं, स्पष्टतया दर्शाता है कि शेयर को स्पष्ट तौर पर बताना होगा। मेरा सुझाव है कि अंतिम उपभोक्ता कीमत में किसान का हिस्सा 50 फीसदी से कम नहीं होना चाहिये।

ऐतिहासिक रूप से लालची वैश्विक मूल्य श्रृंखला द्वारा छोटे भू–मालिकों, किसानों और पशु पालकों को अधिकारपूर्ण देय से वंचित रखा गया। केवल ईयू में ही नहीं बल्कि इस तरह के निर्देश का भारत जैसे देशों और बाकी विकासशील विश्व में भी अनुकरण किया जाना चाहिये। यह उस आय असमानता की खाई को पाटने में मददगार होगा जिससे दुनिया जूझ रही है और नहीं जानती कि इससे बाहर आने की राह क्या है।

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/ensure-farmers-subsistence-income/

भारतीय त्यौहारों का अर्थशास्त्र

सामाजिक एकता को गति देते भारतीय त्यौहार

त्यौहारों का मौसम हिंदू संस्कृति और परंपरा का विशेष उत्सव है। एक और बात जो भारतीय त्यौहार से जुड़ी है, वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इनकी सकारात्मक भूमिका। त्यौहारों का समय बाजार में खरीदारी, तोहफा के आदान–प्रदान, यात्रा और पर्यटन आदि के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड संकट के बाद लगातार सकारात्मक आर्थिक गति को दिखा रही, त्यौहारों में बाजार में बढ़ी हुई मांग और उपभोक्ताओं के उत्साह के कारण अर्थ तंत्र को भी सहयोग मिलता है।

राउटर्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए सर्वे ने भी वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 6 प्रतिशत से ऊपर रखने में त्यौहारों के मौसम में बढ़ी हुई उपभोक्ता मांग और प्रति व्यक्ति खर्च को महत्वपूर्ण माना है। सर्वे के अनुसार वर्ष 2023 का आर्थिक प्रदर्शन इसी कारण से पिछले वर्ष से बेहतर रहेगा।

इसके अलावा डिजिटलीकरण और इंटरनेट क्रांति ने छोटे शहरों में भी ई–कॉमर्स को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिप रॉकेट के अध्ययन के अनुसार ई–कॉमर्स के 56 प्रतिशत से अधिक मांग छोटे और उप नगरी नगरी क्षेत्र से है। आर्थिक आंकड़ों के अनुसार ई–कॉमर्स क्षेत्र में त्यौहारों के मौसम में पिछले वर्ष की अपेक्षा 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी वर्ष ई–कॉमर्स की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने यहां 1.4 बिलियन ग्राहकों की उपस्थिति दर्ज की। वैश्विक स्तर पर भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भारतीय हैंडीक्राफ्ट और ज्वैलरी की मांग में तेजी देखी गई।

हम थोड़ा पीछे जाकर देखें और अपने राष्ट्रीय आंदोलन का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि भारतीय त्यौहारों ने राष्ट्रवाद के जागरण और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। चाहे वह 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन हो, जब दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख उत्सवों ने बंगाली समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ राजनीति जागरूकता और संगठन का संचार किया अथवा महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र और दक्कन के इलाकों में गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति जन जागरूकता फैलाने की बात हो, भारतीय त्यौहार ने राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे मौके पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।

हमारे त्यौहार सामाजिक समरसता, सामुदायिक मिलन और जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक एकता का भी एक सराहनीय उदाहरण है। दुर्गा पूजा, रामलीला और दशहरा मेला जैसे उत्सवों का ग्रामीण भारत से निकलकर शहरों की मुख्य धारा और व्यवहार का हिस्सा बनाना समाज में उनकी बढ़ती स्वीकारता का प्रतीक है।

नोबेल अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्टर डिफ्लो की प्रकाशित पुस्तक Poor Economics (2011) में भी मध्यम वर्ग के लिए त्यौहारों को सामाजिक उत्सव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में मुख्य रूप से– सामूहिक खाद्य संस्कृति, संगीत और कला, नृत्य और नाटक, ऐतिहासिक और संस्कृत पर्यटन (जिसमें हेरिटेज, साइट्स, म्यूजियम, आदि शामिल हैं) जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इन सभी पहलुओं को विभिन्न त्यौहारों के दौरान एक नई ऊर्जा और गति मिलती है जिससे सामाजिक मेल मिलाप और आर्थिक गतिविधियों का प्रचार होता है।

तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारे त्यौहार ने 'बाजार क्रांति' के माध्यम से नई ऊर्जा दी है, जो आने वाले वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लक्ष्य की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा।

– डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह

यूनेस्को के एक आकलन के अनुसार, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत हिस्सा सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग से आता है। अमेरिका जैसे देशों की जीडीपी में तो सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग का योगदान बहुत अधिक है।

त्यौहार छोटे व्यवसायों और स्थानीय विक्रेताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के मौके पर स्ट्रीट बाज़ार, मेले और प्रदर्शनियाँ आर्थिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र बन जाते हैं। छोटे व्यवसाय त्यौहार मनाने और अधिक मुनाफा कमाने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करते हैं क्योंकि त्यौहार के उत्पादों पर अधिक मार्जिन होता है। त्यौहारों का आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष बिक्री से कहीं आगे तक फैला हुआ है। त्यौहारों के आयोजन, आतिथ्य, परिवहन और सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन

त्यौहार छोटे व्यवसायों और स्थानीय विक्रेताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के मौके पर स्ट्रीट बाज़ार, मेले और प्रदर्शनियाँ आर्थिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र बन जाते हैं।

के लिए अक्सर अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होती है। इससे रोजगार के नए अवसर भी जन्म लेते हैं। स्थानीय सरकारें और प्राधिकरण अक्सर त्योहारों की तैयारी के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में निवेश करते हैं।

त्यौहारों के सीज़न के दौरान आगंतुकों की आमद को समायोजित करने के लिए परिवहन नेटवर्क को उन्नत करना, सार्वजनिक स्थानों में सुधार करना और पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाना प्राथमिकताएँ बन जाती हैं। जिसकी वजह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई आर्थिक गतिविधियां, निवेश और रोजगार के कई नए मौके बनते हैं।

कोरोना संकट के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि, जो इसके आर्थिक उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा है, ने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से उबरने में मदद की है, जिसने चीन सहित कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को लड़खड़ा दिया है। विकास को समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे पर अपना वार्षिक खर्च बढ़ा रही है। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में, भारत ने अपने पूंजीगत व्यय बजट का लगभग 28 प्रतिशत खर्च किया था। जाहिर है तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारे त्यौहार ने 'बाजार क्रांति' के माध्यम से नई ऊर्जा दी है, जो आने वाले वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लक्ष्य की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

पर्यावरण और जीवन

पर्यावरण ठीक रहने पर ही मानव जीवन भी ठीक रहता है वरना तो मानव जीवन भी कठिनाई में पड़ जाता है तथा मनुष्य बार बार बीमार पड़ते रहते है। भारत का यह दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनीतिक दल बढ़ते प्रदूषण की तरफ गम्भीरता से ध्यान नहीं देते है तथा वर्ष में एक दो बार पर्यावरण दिवस अथवा किसी अन्य मौके पर पौधारोपण करवा कर राजनीतिक दल अपने कर्तव्य की इति श्री कर लेते है। कोई भी राजनीतिक दल चुनावों में अपने घोषणा पत्र जारी करते समय उन घोषणा पत्रों में पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं लिखते है। पर्यावरण प्रदूषण भी उतनी ही गम्भीर समस्या है जितनी की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बीमारी, मंहगाई आदि। राजनीतिक दलों को अपने अपने कार्यकर्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए उद्‌बोधन करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होती है।

भारत में धीरे धीरे ही सही वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हो रही है। 2017 में 21.54 प्रतिशत, 2019 में 21.67 प्रतिशत, तथा 2021 में 21.71 प्रतिशत वन क्षेत्र था। ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई की बजाय बिजली पर ध्यान दिया जाना चहिए। ईंधन के लिये बिजली का उत्पादन भी गैर पारम्परिक तरीके से हो रहा है। देश में 409 गीगा वाट का कुल बिजली का उत्पादन होता है। जिसमें 6.7 गीगा वाट परमाणु ऊर्जा संयत्रों में, 236 गीगा वाट बिजली का उत्पादन जीवाश्म ईंधन आधारित संयत्रों मे होता है। 166 गीगा वाट बिजली उत्पादन नवीकरणीय स्त्रोतों से होता है। जो इस प्रकार है। 61.9 गीगा वाट सौर ऊर्जा से, 46.8 गीगा वाट बिजली बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से, 41.8 गीगा वाट बिजली का उत्पादन पवन ऊर्जा से होता है। 10.5 गीगा वाट बिजली का उत्पादन बायोमास से तथा 4.9 गीगा वाट बिजली का उत्पादन लधु जल विद्युत परियोजनाओं से स्थापित क्षमता है।

भारत में धीरे धीरे ही सही वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हो रही है। 2017 में 21.54 प्रतिशत, 2019 में 21.67 प्रतिशत, तथा 2021 में 21.71 प्रतिशत वन क्षेत्र था। ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई की बजाय बिजली पर ध्यान दिया जाना चहिए।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने कई लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त कर लिये है। भारत ने 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्त्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था जिस लक्ष्य को 2021 में ही प्राप्त कर लिया गया। इसी प्रकार 33–35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य 2030 तक किया गया है। वर्ष 2021 में ही भारत ने 28 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन तक कटौती का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने कई लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त कर लिये है। भारत ने 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्त्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था जिस लक्ष्य को 2021 में ही प्राप्त कर लिया गया। इसी प्रकार 33–35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य 2030 तक किया गया है। वर्ष 2021 में ही भारत ने 28 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन तक कटौती का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। भारत में पैट्रोल में एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। यह लक्ष्य 20 प्रतिशत तक रखा गया है तथा आशा की जानी चाहिए कि वह भी शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

वन विभाग को चाहिए कि वह वन क्षेत्र में ईको टूरिज्म की परियोजनाओं को चलाये। हरियाली बढ़ेगी तो वन्य जीवो की संख्या भी बढ़ सकेगी तथा आसपास के ग्रामीणों को रोजगार मिल सकेगा। वन्य क्षेत्र में पर्यटकों के लिए केन्टीन व खेल कूद पार्क इत्यादि स्थापित होने से भी रोजगार बढ़ सकेगा। जैव विविधता बढ़ने से विदेशी पक्षियों का भी आगमन हो सकेगा जिनको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते है। वन विभाग को चाहिए कि वह ग्रामीणों को वन व पर्यावरण संरक्षण का भी प्रशिक्षण दे जिससे वे क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के गाइड़ बन सकें।

नहर व रेल लाईनों के किनारे किनारे क्षेत्र में राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा महापुरुषों के जन्म दिवस तथा अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों व दिवसों आदि पर पौधारोपण के कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा आयोजित किये जाने चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण के विकास में तेजी आ सकें।

राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग मात्र आंदोलन व प्रदर्शन इत्यादि आयोजित करने में ही करते है जिससे युवा कार्यकर्ताओं की शक्ति का सद्–उपयोग नहीं हो पाता है। किसी बात के विरोध में आंदोलन करते समय भी खाली पड़ी जमीनों पर पौधारोपण किये जाने चाहिए। आंदोलन में युवा शक्ति का निरर्थक नहीं सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए। देश के पर्यावरण में सुधार पौधारोपण में तेजी लाने से ही बढ़ पायेगा। बस राजनीतिक दलों को अपनी दृष्किोण में थोड़ा बदलाव लाना पडेगा और पर्यावरण में सुधार के लिए सरकार पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। सभी पक्ष व विपक्षी राजनीतक दलों को अपने अपने कार्यकर्ताओं को पर्यावरण की रक्षा तथा संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवम् सामूहिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भारतीय ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को भी पर्यावरण के अनुकूल शीघ्र से शीघ्र व लगातार वृक्षारोपण करवाना चाहिए।❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

...फिर कांपी धरती तो उठे दहलाने वाले सवाल!

नेपाल में 3 नवम्बर 2023 को आए भीषण भूकंप की वजह से डेढ़ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हैं,कई मकान जमीदोंज हो गए हैं, सड़कों में दरारें आ गई है। इससे पहले 8 अक्टूबर को पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के झटको में ढाई हजार से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए थे। इसके ठीक पहले दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र नेपाल में था। उत्तर भारत में उसी दिन धरती लगातार दो बार कांपी थी। इसी साल तुरकिए में भी 7.8 तीव्रतावाला बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस भूकंप ने तुरकिये की जमीन को भी लगभग 3 मीटर तक किसका दिया था।

पिछले एक महीने में यह तीसरी बार है जब भूकंप के जोरदार झटके से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्से के लोग डर कर अपने–अपने घरों से बाहर भागने लगे। बीती रात भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। कई भूगर्भ वैज्ञानिक का शंका जता चुके हैं कि भूकंप के छोटे–छोटे झटके किसी बड़े भूकंप का संकेत भी हो सकते हैं। दिल्ली से बिहार के बीच 7.5 से 8.5 की तीव्रता की बड़े भूकंप की आशंका भी जता चुके हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो भूकंप के झटके बार–बार लगते रहे हैं और इन्हें देखते हुए यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या दिल्ली की ऊंची आलीशान इमारते किसी बड़े भूकंप को झेलने की स्थिति में है? इसके साथ ही यह सवाल भी बार–बार खड़ा होने लगा है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगातार क्यों महसूस होते हैं? यहां रहनेवाले लोगों को चिंता सता रही है कि बार–बार आने वाले झटके किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं है?

ऐसे में भूकंप के किसी बड़े जलजले से बचने के लिए सिर्फ बचाव ही एकमात्र रास्ता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों विशेषज्ञों का यह मानना है कि संवेदनशील इलाकों में इमारत को भूकंप के लिहाज से तैयार किया जाना चाहिए ताकि भूकंप के संभावित नुकसान को कम से काम किया जा सके।

– डॉ. दिनेश प्रसाद

भारत में भूकंप के झटको को लेकर नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह कहा जा चुका है कि जिन 20 भारतीय शहरों तथा कस्बों में भूकंप का खतरा सर्वाधिक है उनमें दिल्ली सहित 9 राज्यों की राजधानियां भी शामिल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र को दुनिया में भूकंप को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और एनसीएस के एक अध्ययन के मुताबिक भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील शहर

इसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। हालांकि एनसीएस की ओर से पिछले महीने यह भी कहा गया था कि खासकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले भूकंप के झटको से घबराने की नहीं बल्कि जोखिम कम करने के उपायों पर जोर देने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे भूकंप आने के समय, स्थिति, तीव्रता की सटीक भविष्यवाणी की जा सके। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली हरिद्वार वन क्षेत्र में खिंचाव के कारण धरती बार–बार हिल रही है। इन झटकों से पता चलता है कि यहां के भूगर्भीय फाल्ट सक्रिय हैं जिसकी वजह से बड़ा भूकंप भी आ सकता है। लेकिन उसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली है जो हिमालय के दक्षिण में है जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। कई अध्ययनों के आधार पर कहा गया है कि 72 प्रतिशत मामलों में हल्के भूकंप ही शक्तिशाली भूकंप के संकेत होते हैं। भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर को संवेदनशील इलाका माना जाता है, जो खतरनाक भूकंप संभावित क्षेत्र 4 में आता है।

दिल्ली में 90 प्रतिशत से अधिक मकान कंक्रीट और सरिया से बने हैं, जिनमें 6 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली का करीब 30 प्रतिशत इलाका भूकंप की दृष्टि से क्षेत्र 5 में आता है, जो सर्वाधिक संवेदनशील है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली में बनी नई इमारतें 6 से लेकर 6.30 तक की तीव्रता झेल सकती हैं जबकि पुरानी इमारते 5 से 5.30 तीव्रता का भूकंप ही सह सकती हैं। कमोबेश सभी विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में जान माल का नुकसान अधिक हो सकता है क्योंकि दिल्ली की

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस के वैज्ञानिक भी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और उत्तरकाशी के इलाकों में बड़े भूकंप की चेतावनी दे चुके हैं। उनके मुताबिक लगभग पूरा उत्तर भारत भूकंप की चपेट में आ सकता है।

आबादी दो करोड़ से अधिक है और प्रति वर्ग किलोमीटर में करीब 10 हजार से अधिक लोग रहते हैं।

किसी बड़े भूकंप का असर करीब 300 किलोमीटर तक दिखता है। वर्ष 2001 में भुज में आए भूकंप के कारण वहां से 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी काफी तबाही हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस के वैज्ञानिक भी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और उत्तरकाशी के इलाकों में बड़े भूकंप की चेतावनी दे चुके हैं। उनके मुताबिक लगभग पूरा उत्तर भारत भूकंप की चपेट में आ सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 2.9 तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है, जबकि 3 से 3.9 तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है मानो कोई भारी ट्रक नजदीक से गुजरा हो। 4 से 4.9 तीव्रता वाले भूकंप में खिड़कियों के शीशे टूटने और दीवारों पर टंगे फ्रेम गिरने लगते हैं। रिक्टर स्केल पर 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को हल्का माना जाता है। 5 से 5.9 तीव्रता के भूकंप में भारी फर्नीचर हिलने लगते हैं और 6 से 6.9 तीव्रता में इमारत की नींव धड़कने से ऊपरी मंजिलों को काफी नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आने पर इमारत के गिरने के साथ जमीन के अंदर की पाइपलाइन भी फट जाती है। 8 से 8.9 तीव्रता का भूकंप आने पर तो इमारत सहित बड़े–बड़े पुल भी गिर जाते हैं, जबकि 9 तीव्रता का भूकंप आने पर हर तरफ तबाही मच जाती है।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को जोन 2 से लेकर जोन 5 में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तर प्रदेश बिहार सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जोन 4 में आता है। जोन 5 में गुजरात का भुज, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र तथा समस्त पूर्वोत्तर भारत आता है।

वैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक पृथ्वी की संरचना टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है जिस पर यह प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार यह प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। बार–बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर यह टूटने लगते हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है जिसके कारण भूकंप आता है। भूकंप कब आएगा? भूकंप कहां आएगा और भूकंप कितनी तीव्रता का आएगा? इसकी सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। हालांकि चीन ने एक समय में दावा किया था कि जानवरों के व्यवहार से भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, मगर यह सरासर झूठ साबित हुआ।

ऐसे में भूकंप के किसी बड़े जलजले से बचने के लिए सिर्फ बचाव ही एकमात्र रास्ता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों विशेषज्ञों का यह मानना है कि संवेदनशील इलाकों में इमारत को भूकंप के लिहाज से तैयार किया जाना चाहिए ताकि भूकंप के संभावित नुकसान को कम से काम किया जा सके। ❑❑

भारत के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में है अपार प्रतिभाः श्रीधर वेंबू

विकसित भारत@2047 के पंच स्तंभ

स्वदेशी शोध संस्थान द्वारा राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की 103वीं जयंती पर गांधी स्मृति, राजघाट, नई दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत@2047 के पंच स्तंभ' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीधर वेंबू ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में अपार प्रतिभा है और यदि हम अनुसंधान, नई तकनीक का उपयोग करें और युवाओं को इसमें प्रशिक्षित करें तो भारत तेजी से रोजगार सृजन व अर्थ समृद्धि कर सकता है। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुंदरम, सह संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा व डॉ. अश्वनी महाजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 'विकसित भारत@2047 के पंच स्तंभ' संगोष्ठी में निम्न विषय केंद्रित रहे।

1. आर्थिक विकास को आकार देने वाले युवा जनसांख्यिकीय लाभांश
2. 2047 के लिए नया आर्थिक प्रतिमानः मानव केंद्रित विकास पर विचार–विमर्श
3. नए भारत के लिए अभेद्य सुरक्षा तंत्र
4. विज्ञान व प्रौद्योगिकी में शीर्ष में आने पर विचार–विमर्श
5. हमारा वैश्विक दृष्टिकोण व जीवन मूल्य

आज दुनिया भारत को किस नज़र से देखती है, चाहे वह उपभोक्ता उत्पादों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना हो, वैक्सीन, यूपीआई की सफलता, हंगर इंडेक्स जैसी रिपोर्टों द्वारा विमर्श को ठीक दिशा देनी होगी। इसके अतिरिक्त, रक्षा तैयारी और सॉफ्ट पावर की प्रासंगिकता जैसे– फिल्में, साहित्य, कथा निर्माण और नीति निर्माण में प्रचार, क्षमता और जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन, स्थानीय स्तर पर जिला केंद्रित योजना और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

यह राष्ट्रीय संगोष्ठी पंच सत्र में संचालित हुई। जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार, टीवी–9 नेटवर्क के कार्यकारी संपादक श्री आदित्य राज कौल, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के प्रसिद्ध रक्षा नीति विशेषज्ञ डॉ. राजीव नयन, एच.ए.एल. के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर.के. त्यागी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल, फिल्म इतिहासकार एवं लेखक श्री गौतम चिंतामणि, श्री शिवशक्ति बख्शी, डॉ. संजीव जोशी, प्रो. अमिता देवी, प्रो. सपना पोती, डॉ. नवीन बल्ली, श्री विनय गोयल, श्री शौर्य डोभाल, एनआईईपीए के वीसी प्रो. शशि वंजारी, डीएसई से प्रो. रामसिंह, सीए श्री राजीव सिंह, श्री गगन कुमार, चैन्नई से श्रीमती मैथिली, रक्षा मंत्रालय से शिवाली चौहान आदि विभिन्न सत्रों में मंचस्थ रहे। स्वदेशी शोध संस्थान से सीए अनिल शर्मा, प्रो. प्रदीप चौहान, प्रो. सरबजीत कौर व विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में युवा, एनएसएस के छात्र–छात्रा उपस्थित रहे। ❑

भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट्स के प्रकाशन पर लगे रोकः स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि सरकार को भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट्स के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने के लिए भारत सरकार को राजनयिक स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मंच ने भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियों के साथ भी इस मुद्दे को उठाने की मांग की।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने जर्मन संस्था वेल्ट हंगरहिल्फ़े द्वारा जारी हंगर इंडेक्स को वैश्विक भूख सूचकांक पर एक और शरारतपूर्ण रिपोर्ट करार देते हुए यह आरोप लगाया कि पिछले वर्षों की तरह एक बार फिर जर्मन संस्था वेल्ट हंगरहिल्फ़े ने अपना हंगर इंडेक्स और उसी के आधार पर दुनिया के देशों की भुखमरी रैंकिंग प्रकाशित की है। इस रैंकिंग में भारत को एक बार फिर बेहद निचले पायदान 111 वीं रैंकिंग पर रखा गया है। इस साल इस रैंकिंग में 125 देशों को शामिल किया गया है। पिछले साल 2022 में भारत 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर था और 2021 में 116 देशों की रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर था।

महाजन ने कहा कि इस रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों का प्रदर्शन भारत से कहीं बेहतर है, जो खुद भारत से खाद्य आपूर्ति पर निर्भर हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि हम भोजन के उत्पादन और उपलब्धता पर विचार करें तो 188 देशों की नवीनतम वैश्विक रैंकिंग (2020) में भारत दुनिया में 35वें स्थान पर है। खाद्यान्न, दूध, अंडे, फल, सब्जियां, मछली आदि का प्रति व्यक्ति उत्पादन लगातार बढ़ रहा है जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारत आज मांग की तुलना में पर्याप्त या अधिशेष भोजन का उत्पादन कर रहा है।

उन्होंने दावा किया कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा अनुमानित भूख सूचकांक 9.528 निकलता है। इस हिसाब से वेल्ट हंगरहिल्फे के फॉर्मूले के मुताबिक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग 111वीं नहीं बल्कि 48वीं होगी।

स्वदेशी जागरण मंच के नेता ने इस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के प्रति गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के देशभक्त लोगों को दुर्भावनापूर्ण इरादों वाली ऐसी रिपोर्टों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और साथ ही वे भारत सरकार से इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाने और भविष्य में भारत को बदनाम करने वाली ऐसी रिपोर्टों के प्रकाशन पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, अपने संबंधित डेटा सेट में सुधार में तेजी लाने के लिए इस मुद्दे को खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ भी उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुपोषण के बारे में वेल्ट हंगरहिल्फे के पास कोई तथ्यात्मक और विश्वसनीय डेटा नहीं है, क्योंकि संबंधित आधिकारिक एजेंसी द्वारा घरेलू उपभोग सर्वेक्षण 2011 के बाद से नहीं किया गया है। लेकिन, दुर्भाग्य से वेल्ट हंगरहिल्फे की रिपोर्ट कुपोषण का आंकड़ा 16.6 प्रतिशत बता रही है। इस संदर्भ में, भारत सरकार की पहल, पोषण ट्रैकर ने योजना के तहत शामिल 7 करोड़ से अधिक बच्चों से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के आधार पर डेटा प्रकाशित किया है।

पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार फरवरी में बच्चों में कुपोषण 7.7 है। जनसंख्या में कुपोषण का बच्चों में कुपोषण से बहुत अधिक अंतर नहीं हो सकता है। हाल तक, केवल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) द्वारा मूल्यांकन किए गए स्टंटिंग और वेस्टिंग पर डेटा देश में उपलब्ध था, जिस पर इसके छोटे नमूना आकार के कारण सवाल उठाए गए थे। जबकि, एनएफएचएस अपेक्षाकृत छोटे नमूने के आधार पर निष्कर्ष निकालता था, पोषण ट्रैकर 7 करोड़ से अधिक बच्चों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर डेटा प्रकाशित कर रहा है, जिसमें वेस्टिंग डेटा लगातार दिखा रहा है कि भारत के केवल 7.2 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग का शिकार थे।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेल्ट हंगरहिल्फ़ की हंगर रिपोर्ट (2023) ने 18.7 प्रतिशत के एनएफएचएस 2019–21 के आंकड़े का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं सरकार का पोषण अभियान देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पोषण ट्रैकर द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

https://www.newsnationtv.com/india/20231018194205-413219.html

छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन

गोपाल विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में दीपावली के उपलक्ष्य में रविवार को सांस्कृतिक स्वदेशी मेला लगाया गया। स्वदेशी जागरण मंच जिला जींद के द्वारा आयोजित इस प्रथम मेले में लगाई गई 50 स्टालों में स्वदेशी उत्पाद व अन्य चीजों को दर्शाया गया और हजारों लोगों ने इस मेले का लुत्फ उठाया। लोगों ने मेले से जमकर सामान भी

खरीदा। इस मेले में समाज सेवी पवन गर्ग ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। इस मेले में समाज सेवी पवन सिंगला, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ. राज सैनी, सुरेंद्र कुमार, स्वदेशी जागरण मंच हिसार के जिला संयोजक संजीव शर्मा, प्रांतीय प्रचार प्रमुख अनिल गोयल, हिसार नगर प्रचार प्रमुख विनय हसीजा ने विशेष रूप से भाग लिया।

अध्यक्षता स्वदेशी जागरण मंच जींद के जिला संयोजक राजेंद्र गुप्ता ने की। इस मेले में हरियाणा की प्रसिद्ध कलाकार ममता शर्मा ने हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सब का मन मोह लिया। सिर पर हुक्का व हुक्का पर दो टोकनी रख कर दामन, चुंदड़ी पहने हरियाणवीं वेशभूषा में महिला कलाकार ममता शर्मा ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ–साथ स्वदेशी चीजों को अपनाने का संदेश दिया।

पवन गर्ग ने कहा कि यह संस्था द्वारा अच्छा प्रयास है और स्वावलंबन की ओर बढ़ती अनुकरणीय पहल है। इससे लोगों में संस्कृति व कला के साथ स्वदेशी चीजों के प्रति जागृति बढेगी। संजीव शर्मा व डा. राज सैनी ने भी इस पहल के लिए स्वदेशी जागरण मंच जींद की पूरी टीम एवं अन्य सामाजिक व स्वयं सेवी संस्थाओं की सराहना की और अपने विचार प्रकट किए। इस मेले में बच्चों द्वारा मनोहारी व शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

https://www.amarujala.com/haryana/jind/50-stalls-set-up-in-swadeshi-fair-to-promote-small-entrepreneurs-jind-news-c-199-1-sroh1006-8025-2023-10-30

विदेश पढ़ने जाने वालों की बढ़ती संख्या चिंताजनक

स्वदेशी जागरण मंच ने हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पर चिंता जताई है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि पिछले 30 सालों में यह संख्या दस गुना बढ़ गई है।

महाजन ने लिखा, "केंद्र सरकार के मुताबिक, 2016 से 2021 के बीच 26.44 लाख भारतीय छात्र विदेश पढ़ने गए। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचम) का अनुमान है कि साल 2020 में 4.5 लाख भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और उन्होंने 13.5 अरब डॉलर खर्च किए। साल 2022 में ये खर्च 24 अरब डॉलर यानी; लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह खर्च 2024 तक 80 अरब डॉलर या 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। जब अनुमानित 20 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई करेंगे।"

उन्होंने आगे लिखा, "युवा छात्र नौकरी पाने की उम्मीद में विदेशों में जाते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि आज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के शैक्षणिक संस्थान उन्हें अपने अस्तित्व के लिए आसानी से प्रवेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत और अन्य देशों के इच्छुक छात्रों से भारी फीस वसूलने के लिए कई शिक्षा 'दुकानें' खोली जा रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई लेना–देना नहीं है।"

महाजन ने कहा कि यह देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी जब 2024 तक विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या 20 लाख तक पहुंच जाएगी और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी।

उन्होंने कहा, "ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को युवाओं को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है ताकि वे विदेश जाकर अपने माता–पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें।"

हमास की आतंकी विचारधारा का समर्थन देशहित के विरुद्धः एबीवीपी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कहा कि शैक्षिक परिसरों में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा इस तरह की किसी भी प्रकार की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं।

एक प्रेस नोट में एबीवीपी ने कहा कि पिछले हफ्ते इज़रायल पर हुए हमले पर कुछ राजनीतिक दलों और समूहों की चुप्पी "बौद्धिक दिवालियापन" का संकेत है।

एबीवीपी के प्रेस नोट में कहा गया, "देश के विभिन्न संगठनों को भारत सरकार की वर्तमान विदेश नीति के अनुरूप अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। धार्मिक कट्टरता और पूर्वाग्रहों के चलते हिंसा की इस चरम स्थिति पर आंख मूंदकर अपना ही राग अलापने वाले संगठनों से सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में हमास द्वारा इज़रायल पर किए गए आतंकवादी हमले पर एक अलग टिप्पणी करने का प्रयास किया जा रहा है और यह हमास की आतंकी विचारधारा का समर्थन करने जैसा है।"

डिजिटल मीडिया हाउस न्यूज़क्लिक पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी और इसके संस्थापक और एचआर प्रमुख की गिरफ़्तारी और भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद भी उन मुद्दों में से थे जिन्हें हिंदू राइट प्रेस ने पिछले सप्ताह कवर किया और उसपर टिप्पणी की।

https://hindi.theprint.in/india/education-shops-extorting-indian-students-hindu-right-press-warns-against-study-abroad-trend/614320/

भारत में लगातार घट रही है गरीबों की संख्या

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय और संपत्ति में असमानता के मामले में भारत कुछ शीर्ष देशों में शामिल है। हालांकि 2015 से 2019–21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से गिरकर 15 प्रतिशत हो गई है।

जारी की गई 2024 एशिया–प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट न केवल दीर्घकालिक प्रगति के साथ असमानता की तस्वीर पेश करती है, बल्कि मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करती है। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय 442 डालर से बढ़कर 2,389 डालर हो गई। जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर (प्रतिदिन 2.15 डालर के अंतरराष्ट्रीय गरीबी माप के आधार पर) 40 से गिरकर 10 प्रतिशत हो गई।

डायरेक्शन फार ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक के शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी को कम करने में सफलता जरूर मिली है, लेकिन यह उन राज्यों में ज्यादा है, जहां देश की 45 प्रतिशत आबादी रहती है। यहां पर देश के 62 प्रतिशत गरीब रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर हैं। जिन समूहों के दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है, उनमें महिलाएं, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर–राज्य प्रवासी शामिल हैं।

महिलाएं श्रम शक्ति का केवल 23 प्रतिशत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से विकास के बीच आय वितरण में असमानता बढ़ी है। मुख्य रूप से वर्ष 2000 के बाद की अवधि में संपत्ति में असमानता में बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत वैश्विक मध्यम वर्ग (12 डालर से 120 डालर के बीच जीवनयापन करने वाले लोग) की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एशिया–प्रशांत क्षेत्र इस साल वैश्विक आर्थिक विकास में दो–तिहाई का योगदान देगा।

https://www.jagran.com/business/biz-number-of-poor-decreased-by-10-percent-in-six-years-23574721.html

भारतीय अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर से बढ़ी चीन की टेंशन!

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर है। रेटिंग एजेंसी फिच ने मिड–टर्म ग्रोथ रेट को 70 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने 6.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। पहले यह 5.5 प्रतिशत था। भारत के अलावा मैक्सिको के मीडियम टर्म ग्रोथ रेट में भी इस अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी ने इजाफा किया है।

फिच की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमने मैक्सिको और भारत की रेटिंग में बड़ा इजाफा किया है। लेबर कैपिटल रेशियो की वजह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। भारत के लिए अनुमान 5.5 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत और मैक्सिको के लिए 1.4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

रेटिंग एजेंसी ने पोलैंड का मिड टर्म ग्रोथ रेट 2.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत, टर्की ने 3.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.1 प्रतिशत और ब्राजिल का 1.5 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, इंडोनेशिया का ग्रोथ रेट अनुमान 4.7 प्रतिशत से 4.9 प्रतिशत कर दिया गया है।

वहीं, चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिच ने चीन का मिड टर्म ग्रोथ रेट 5.3 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया है। रूस की ग्रोथ रेट को 1.6 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत कर दिया गया है। कोरिया को 2.3 प्रतिशत से 2. 1 प्रतिशत और साउथ अफ्रीका का 1.2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। ❑❑

https://www.livehindustan.com/business/story-fitch-mid-term-growth-rate-data-released-good-news-for-indian-economy-8943300.html

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

प्रांत पूर्णकालिक प्रशिक्षण वर्ग

दिल्ली – अक्टूबर 27–29, 2023

सचित्र झलक

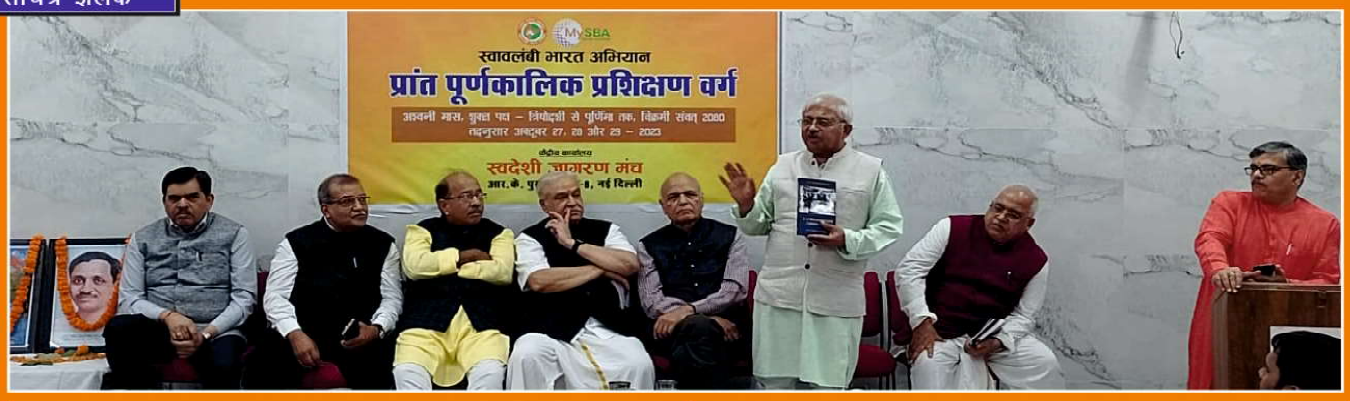

स्वदेशी मेला – दिल्ली

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 नवंबर 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

Entrepreneurship Encouragement Conferences

सचित्र झलक

शिमला, हिमाचल प्रदेश

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

भोपाल, मध्य प्रदेश

सीटीयू, लुधियाना, पंजाब

सिमडेगा, झारखंड

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती